www.ghoonghatkibagawat.com ghoonghatkibagawat37@gmail.com ghoonghatkibagawat.com

UP/HIN/1999/1282

घूँघट की बगावत

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित हिन्दी (साप्ताहिक समाचार पत्र)

वर्ष : 23 | अंक : 46 | गोरखपुर | 26 मई 2024 | पृष्ठ : 08 | मूल्य: 2/-

इंडी गठबंधन के दलों की राजनीति हिंदू विरोधी

कीमत कोई भी हो,चाहतें हैं सत्ता: योगी आदित्यनाथ

गोरखपुर (जीकेबी)। सीएम योगी ने कहा कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ, दोनों भारत की प्रतिष्ठित धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं हैं। रामकृष्ण मिशन ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर पूरे देश और दुनिया के अंदर सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों को, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया है।

भारत सेवाश्रम संघ, रामकृष्ण मिशन जैसी वैश्विक ख्याति की सनातनी-आध्यात्मिक संस्थाओं पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी समेत पूरे इंडी गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस, टीएमसी, राजद, सपा और इंडी गठबंधन के सभी दल हिंदू विरोध की राजनीति करते हैं। शनिवार पूर्वाह्न लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए बलिया रवाना होने से पहले गोरखनाथ मंदिर परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस और उसके जो भी सहयोगी दल हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बिहार में आरजेडी, बंगाल में टीएमसी या अन्य ऐसे भी जितने दल हैं, उनकी पूरी राजनीति ही हिंदू विरोध पर आधारित है। उनके लिए देश की तुलना में सत्ता अधिक महत्वपूर्ण है। देश की कीमत पर ये दल सत्ता चाहते हैं और कोई भारतीय इसे स्वीकार नहीं करेगा। पश्चिम बंगाल में भारत सेवाश्रम संघ और रामकृष्ण मिशन के खिलाफ टीएमसी सरकार की मुखिया ममता बनर्जी के विवादित और धमकी भरे बयान को संदर्भित करते हुए सीएम योगी ने कहा कि रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ, दोनों भारत की प्रतिष्ठित धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाएं हैं। रामकृष्ण मिशन ने स्वामी विवेकानंद के आदर्शों पर चलकर पूरे देश और दुनिया के अंदर सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों को, भारत के आध्यात्मिक मूल्यों को देश और दुनिया तक पहुंचाने का बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। इसी तरह भारत सेवाश्रम संघ भी सनातन हिंदू धर्म की बहुत ही प्रखर आध्यात्मिक संस्था है। स्वामी प्रणवानंद के मूल्यों और आदर्शों को लेकर भारत सेवाश्रम संघ ने देश और दुनिया में भारत के सनातन धर्म के मूल्यों और आदर्शों के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य किया है।

इसके साथ ही इन दोनों संस्थाओं ने सेवा के विभिन्न प्रकल्पों को भी देश और दुनिया के अंदर आगे बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के सभी दलों कांग्रेस, सपा, टीएमसी, आरजेडी, आम आदमी पार्टी आदि की प्रवृत्ति ही हिंदू विरोधी राजनीति की है। सनातन धर्म का विरोध करना, हिंदू धर्म के मूल्यों और आदर्शों का विरोध करना स्वाभाविक रूप से उनकी नींव में है और उसी के अनुरूप उनके बयान और कदम सामने आ रहे हैं। ये बयान उनकी हार की बौखलाहट को प्रदर्शित करते हैं।

सीएम योगी ने कहा कि जिस स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, जिस रामकृष्ण मिशन और भारत सेवाश्रम संघ ने अध्यात्म और संस्कृति के जिस वृहद जागरण अभियान को देश-दुनिया मे बहुत ही अच्छे सेवा प्रकल्पों के साथ आगे बढ़ाया है, उससे जुड़े अनुयायी और श्रद्धालु कांग्रेस, टीएमसी और इंडी गठबंधन को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्हें कहा कि जैसे रावण के समय में ऋषि मुनियों को धमकी दी जाती थी, उसी प्रकार की स्थिति इनके द्वारा पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। पर, सनातन धर्म इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाला नहीं है और इसका मुंहतोड़ जवाब देगा।

ओबीसी आरक्षण में सेंधमारी के लिए माफी मांगे टीएमसी सरकार

सीएम योगी ने कहा कि एक तरफ इंडी गठबंधन के दल हिंदुओं की धार्मिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को धमकी दे रहे हैं तो दूसरी तरफ पिछड़ी जाति के लोगों के अधिकारों का जबरन बंदरबांट करने का काम कर रहे हैं। टीएमसी सरकार ने पश्चिम बंगाल के अंदर वर्ष 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके ओबीसी के आरक्षण पर सेंधमारी की थी। पिछले 14 वर्षों में पिछड़ी जाति के लाखों लोग आरक्षण की सुविधाओं से वंचित हुए होंगे। इसके लिए ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार को और कांग्रेस को ओबीसी समुदाय से माफी मांगनी चाहिए। जिन युवाओं, जिन नागरिकों के अधिकार छीनने का यह कृत्य किया गया है, वह किसी भी स्थिति में स्वीकार योग्य नहीं है। दूसरा यह बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की भावना के विपरीत है। भारतीय संविधान के शिल्पी डॉ. अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता।

कोलकाता उच्च न्यायालय का निर्णय इंडी गठबंधन के दलों पर जोरदार तमाचा

सीएम ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण भारत के एक और विभाजन के षड्यंत्र का हिस्सा है। कोलकाता उच्च न्यायालय ने जो निर्णय लिया है वह अत्यंत सराहनीय और अभिनंदनीय है। उच्च न्यायालय का यह निर्णय टीएमसी, कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों के मुंह पर जोरदार तमाचा है।

बीजेपी और कांग्रेस का घोषणा पत्र सिर्फ छलावा: मायावती

गोरखपुर (जीकेबी)। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गोरखपुर में चुनावी जनसभा में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। कहा कि बीजेपी, कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों का चुनावी घोषणा पत्र सिर्फ छलावा होने के साथ हवा हवाई है। बीएसपी चुनाव में घोषणा पत्र जारी करने में नहीं सत्ता में आने पर काम करने में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी दल पूंजीपतियों एवम् धन्ना सेठों के पोषक हैं। इसका खुलासा इलक्ट्रोलबॉन्ड से हो चुका है। सपा पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा आरक्षण विरोधी है। सत्ता में रहते हुए उसने पदोन्नति में आरक्षण को समाप्त किया। जिसका जवाब जनता देगी। मायावती शनिवार को गोरखपुर के रामगढ़तल क्षेत्र के चंपा देवी पार्क में चुनावी सभा को संबोधित कर रही थी।

दिग्गज नेताओं का भविष्य ईवीएम में बन्द

नई दिल्ली(जीकेबी)। लोकसभा चुनाव में छठें चरण का मतदान हिंसा की छिटपुट घ ाअनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। छठे चरण में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सभी सात सीटों समेत केन्द्र शासित प्रदेशों और आठ राज्यों की 38 सीटों पर शाम छः बजे तक 59 प्रतिशत मतदान हुआ। सर्वाधिक मतदान 77.99 प. बंगाल, उत्तर प्रदेश (54 प्रतिशत) बिहार में (52.24 प्रतिशत), और झारखंड में 61.41 प्रतिशत लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

सूत्रानुसा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज (49.30)अंबेडकर नगर (59.53), बस्ती (55.03), भदोही (50.67), डुमरियागंज (46.80), लालगंज (52.86), मछलीशहर (52.10), फूलपुर (46.80), संतकबीरनगर (51.11) श्रावस्ती (50.71) और सुलतानपुर में 53.67 प्रतिशत मतदान हुआ। वहीं बिहार के गोपालगंज में (46.77), वैशाली (56.11), महराजगंज(49.15), प.चंपारण(55.22)पूर्वी चंपारण (55.78), सीवान (47.49), शिवहर (54.37) और वाल्मीकिनगर में 54.09 प्रतिशत मतदान हुआ। जबकि झारखंड के धनबाद में (58.75) प्रतिशत का मतदान हुआ।

इंडी गठबंधन के प्रत्याशी के समर्थन में नेत्रीद्वय ने झोंकी ताकत

वाराणसी(जीकेबी)। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री प्रियंका गांधी वाड्र और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिम्पल यादव पहली बार वाराणसी की सड़कों पर एक साथ दिखाई दीं। दोनों ने इंडी गठबंधन प्रत्याशी के समर्थ में रोड शो के माध्यम से जनसमर्थन और वोट मांगा।

महंगाई और बेरोजगारी की बात न करने वालों को रास्ता दिखाना होगा: प्रियंका वाड्रा

गोरखपुर (जीकेबी)। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड़ा ने शनिवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर जमकर जुबानी हमला बोला। प्रधानमंत्री की बिहार में हुई जनसभा का हवाला देते हुए कहा, मोदी ने बिहार में विपक्ष के नेताओं के लिए ऐसे-ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो देश के इतिहास में आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। प्रधानमंत्री पद का पूरा देश आदर करता है, हम भी करते हैं। प्रधानमंत्री बौखलाहट में आ गए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद की मर्यादा और गरिमा नहीं रखी। सहारा एस्टेट के क्रिकेट मैदान पर बांसगांव से कांग्रेस प्रत्याशी सदल प्रसाद और गोरखपुर से सपा प्रत्याशी काजल निषाद के समर्थन में जनसभा कर रहीं प्रियंका ने कहा कि आज देश की सबसे बड़ी समस्या महंगाई और बेरोजगारी है। क्या मोदी जी इस पर बात करते हैं, उनके मुख से कभी बेरोजगार श्शब्द सुना? जवब मिला नहीं। कहा, तीन महीने से पीएम प्रचार कर रहे हैं, लेकिन उनके मुंह से महंगाई शब्द नहीं निकला। एक सवाल उन्होंने किया क्या समय आ गया है कि मोदी को हम बताएं कि बेरोजगारी क्या होती है प्रधानमंत्री गरीब और किसान विरोधी सरकार चला रहे हैं बेरोजगारी और महंगाई की बात न करने वालों को रास्ता दिखाना होगा।

जाम और दुर्घटना का कारण बनते ई-रिक्शा

संवाददाता,

गोरखपुर। इसे विभागीय उदासीनती कहें या वाहन स्वामियों की लापरवाही।

जिले में लगभग दस हजार ईरिक्शा पंजीकृत हैं, इनमें से तीन हजार अनफिट हैं, जो हर पल दुर्घटना को दावत दे रहे हैं। एक तो चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं हैं, ऊपर से यातायात के नियमों का पालन भी नहीं कर रहे।

अनफिट ई-रिक्शा महानगर में

दुर्घटना ही नहीं जाम के कारण भी बनते जा रहे हैं। स्थिति यह है कि पंजीकृत ई-रिक्शे के लिए लगभग 50 चालकों के पास ही ड्राइविंग लाइसेंस है।

12 से 16 साल के बच्चे ही नहीं, 60 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ भी बिना लाइसेंस के ई-रिक्शा लेकर दौड़ रहे हैं। इसका खामियाजा आमजन को भुगतना पड़ रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक चालक ई रिक्शा और ऑटो सफेद तथा सीएनजी 40 ऑटो हरे रंग की ही पंजीकृत किया जा रहे हैं। ई रिक्शा के लिए जॉन और रूट निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है और फिट वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है पकड़े जाने पर कार्रवाई की जा रही है।

अरुण कुमार

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी गोरखपुर

ई रिक्शा चालक मनमानी तो कर ही रहे,

परिवहन विभाग भी उदासीन बना हुआ है। परिवहन विभाग में अब सफेद रंग के ई-रिक्शे का ही पंजीकरण और फिटनेस प्रमाण पत्र बन रहा है। ऐसे. में जो वाहन स्वामी रंगीन ई-रिक्शा चला रहे हैं, वे फिटनेस प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के बाद भी लापरवाह बने हुए हैं । वे न ई-रिक्शा का रंग बदलकर सफेद करा रहे और न ही फिटनेस जांच करा रहे हैं। भले ही परिवहन विभाग ने लाल, पीला, हरा, बैंगनी आदि रंगीन ई-रिक्शे के पंजीकरण और फिटनेस जांच पर रोक लगाकर सफेद रंग का ई-रिक्शा में अनिवार्य कर दिया है लेकिन महानगर की सड़क और चौराहों पर रंग-बिरंगे रिश्ते दिखाई दे रहे हैं।

17 माह के बाद भी निश्चित नहीं हो पाया रूट-

एक दिसंबर 2022 को संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में ई रिक्शा संचालन के लिए जोड़ स्वरूप निर्धारण किया गया था लेकिन एक माह के अंदर प्रक्रिया पूरी होनी थी जो 17 माह से अधिक हो गए राज्य स्थिति यह है कि ई-रिक्शा महानगर की सड़कों चौराहा हो और गलियों में मनमाने ढंग से चल रहे हैं कुछ लोगों ने ई रिक्शा को व्यवसाय बना लिया है। एक संचालक पर दो-दो दर्जन ई रिक्शा है नियम अनुसार फिटनेस जांच नहीं करते हैं

जबकि ई रिक्शा का प्रत्येक 2 साल पर फिटनेस जांच अनिवार्य होता है।

देश की सीमा हमारी संप्रभुता को परिभाषित करती है : अजीत डोभाल

बीएसएफ का अलंकरण समारोह

नई दिल्ली। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कहा कि पिछले दस सालों में देश तेजी से सशक्त हुआ है। हालांकि अगर हमारे देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित, सुरचित और प्रतिकूल है कब्जेवाली नहीं होतीं, तो भारत ने अधिक रफ्तार से प्रगति की होती। उन्होंने कहा, श्जमीन पर जो कब्जा है वही अपना है, बाकी तो सब अदालत का काम है। उससे फर्क नहीं पड़ता। 21वें अलंकरण समारोह में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की ओर से आयोजित रुस्तमजी मेमोरियल लेक्चर में शुक्रवार को एनएसए डोभाल ने कहा कि भारत की आर्थिक प्रगति अधिक रफ्तार पकड़ती अगर देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित रहतीं। इसलिए सीमाओं पर तैनात सैन्य बलों के कंधों पर अत्यधिक भार आ गया है। उन्हें हमेशा 24ः7 सतक रहना पड़ता है। उन्हें हर वक्त हमारे राष्ट्रीय हितों और देश की सुरक्षा का ख्याल रखना पड़ता है। देश की सीमाएं अधिक महत्वपूर्ण है इसलिए कि वह हमारे संप्रभुता को परिभाषित करती है। उपस्थित लोगों को उन्होंने बताया कि पिछले 10 सालों में भारत सरकार ने सीमाओं की सुरक्षा पर बहुत ध्यान दिया है हमारी ताकत बड़ी है भारत बहुत तेजी से बदल रहा है।

आगामी 10 वर्षों में हम 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनामी हो जाएंगे साथ ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। भारत के पास सबसे बड़ा कार्यबल है उच्च तकनीक के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर क्वांटम कंप्यूटिंग और रक्षा व सुरक्षा निर्माण के विभिन्न क्षेत्रों में भारत के पास हब होगा इससे बदलते भारत में समृद्धि कुछ हद तक सुरक्षा की भी गारंटी बनेगी।

उत्तर प्रदेश से मात्र 38 सांसद निर्दलीय

आजादी के बाद से अब तक के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से मात्र 38 सांसद निर्दलीय चुने गए हैं। डेढ दशक पहले आखिरी बार वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह एटा लोकसभा सीट से बतौर निर्दलीय सांसद चुने गए थे। हालांकि, उनहें सपा का समर्थन हासिल था। आपात काल के बाद वर्ष 1977 के चुनाव में 248, इंदिरागांधी की हत्या के बाद वर्ष 1984 के चुनाव में 888 और मंडल कमीशन व राम मंदिर आंदोलन के दौरान वर्ष 1991 में, हुए चुनाव में 1016 उम्मीदवार निर्दलीय ही चुनाव मैदान में तो उतरे, लेकिन तीनों ही चुनाव में किसी को कामयाबी नहीं मिली थी। इस बीच 1989 के चुनाव में दो और अन्य चुनाव में एक-एक निर्दलीय सांसद राज्य से चुना गया था।

वर्ष 1989 में बलरामपुर से निर्दलीय उम्मीदवार मुन्नन खान और गाजीपुर से जगदीश सांसद बनने में कामयाब रहे। रिकार्ड आठ बार की सांसद और एक बार फिर सुलतानपुर से भाजपा प्रत्याशी मेनका गांधी भी एक नहीं दो बार बिना किसी दल के सहारे सांसद चुनी जा चुकी हैं। 1998 व 1999 में पीलीभीत के मतदाताओं ने दलीय प्रत्याशियों से मुंह मोड़ते हुए मेनका को अपना सांसद चुना था। दो दशक पहले वर्ष 2004 के चुनाव में उतरे 1138 प्रत्याशियों में 481 निर्दलीय ही थे। ध्यातव्य है कि एक मात्र निर्दलीय उम्मीवार हरीश नागपाल ने अमरोहा लोकसभा सीट पर रालोद के महमूद मदनी को शिकस्त देकर जीत हासिल की थी। निर्दलीय चुनाव जीतने वाली बड़ी हस्तियों में पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी हैं। अमिताभ बच्चन के इस्तीफे के बाद वर्ष 1988 के उपचुनाव में वीपी सिंह इलाहाबाद से निर्दलीय ही जीते थे।

व्यक्तिगत जनाधार और लोकप्रियता के दम पर ही गोरखपुर सीट से दिग्विजय नाथ और फिर महंत अवैद्यनाथ भी निर्दलीय सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं। वर्ष 1967 के चुनाव में लखनऊ से निद. लीय आनंद नारायण मुल्ला तो कानपुर से एसएम बनर्जी भी तीन बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर सांसद चुने गए।

व्यक्तिगत जनाधार और लोकप्रियता के दम पर ही गोरखपुर सीट से दिग्विजय नाथ और फिर महंत अवैद्यनाथ भी निर्दलीय सांसदी का चुनाव जीत चुके हैं। वर्ष 1967 के चुनाव में लखनऊ से निर्दलीय आनंद नारायण मुल्ला तो कानपुर से एसएम बनर्जी भी तीन बार आजाद उम्मीदवार के तौर पर सांसद चुने गए। गौरतलब है कि हाल के वर्ष में जातीय राजनीति करने वाले क्षेत्रीय दलों का दबदबा बढ़ा है। बड़ी पार्टियां भी इन दलों से गठबंधन कर उन्हें साधने में पीछे नहीं है। ऐसे में अब बिना किसी दल का दामन थामे सिर्फ खुद की शख्यिसत व लोकप्रियता के दम पर चुनाव जीतना आसान नहीं दिखता, फिर भी इस बार चुनाव मैदान में उतरे 851 प्रत्याशियों में से निर्दलीय 277 में से कौन सभी दलीय उम्मीदवारों को धूल चटाने में कामयाब होता है यह तो चार जून को मतों की गणना के बाद ही पता चलेगा।

साथी अग्निवीरों के लिए रोल मॉडल बनें अग्निवीर

बेंगलुरु। चीफ आफ डिफेस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने अग्निवीरों से कहा के वह सैन्य सेवा में बहत ही महान उद्देश्य कीपूर्ति के लिए आए हैं। सैन्य ढांचे में उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण और बुनियादी है। अग्निवीर सिर्फ सैनिक ही नहीं बल्कि नेता, अन्वेषक और देश की संप्रभुता के रक्षक हैं। उन्होंने व्यवसाय के रूप में सैन्य बलों को चुनने की प्रतिबद्धता दिखाने के लिए अग्निवीरों का आभार जताया। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सोमवार को बेलगावी में मराठा लाइट इनफैंट्री रेजिमेंटल सेंटर में सेना में अपनी शुरुआत करने वाले अग्निवीरों को संबोधित किया। रक्षा विभाग की ओर से जारी बयान के अनुसार जनरल अनिल चौहान ने आश्वासन दिया की चुनौतियों के बावजूद अग्नि वीरों का यह सफर प्रत्येक चरण में बहुत ही लाभप्रद रहेगा इसमें उनके व्यक्तित्व के विकास के साथ ही राष्ट्र की सेवा करने में उन्हें अत्यधिक गौरव का अनुभव होगा। उन्होंने अग्नि वीरों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वह इसी तरह बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए तात्पर्य है साथियों अपने साथी अग्नि वीरों के लिए रोल मॉडल बनें । उन्होंने अपने संबोध न में युद्ध की प्रकृति में बदलाव की बात करते हुए जटिलताओं और भाभी युद्धों के अनिश्चितताओं पर विशेष बल दिया।

समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है भारत विकास परिषद

पडरौना(कुशीनगर)। भारत विकास परिषद समाज के अंतिम व्यक्ति की चिंता करती है। इससे जुड़े साधन संपन्न लोगों की ओर से समाज के सबसे निचले स्तर पर सुविधाएं व सेवा उपलब्ध कराई जाती है। जरूरतमंदों को सुविधा प्रदान करना, उनकी स्वास्थ्य की देखभाल करना और आवश्यकता की आपूर्ति करने के साथ ही शिक्षा और संस्कार देना परिषद का उद्देश्य है। ये बातें राज्यसभा सदस्य व पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री कुंवर आरपीएन सिंह ने कहीं। वे सोमवार को हनुमान इंटर कॉलेज परिसर में आयोजित परिषद की तथागत शाखा कुशीनगर के पदाधिकारियों के दायित्व ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आगे भारत विकास परिषद की तरफ से किए जाने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इसके बाद तथागत शाखा के अध्यक्ष डॉ. राजीव कुमार मिश्र, सचिव राधा रमन गाड़िया, कोषाध्यक्ष मनोज शर्मा सारस्वत, महिला संयोजक दीपाली श्रीवास्तव ने दायित्व ग्रहण किया। कार्यक्रम को सदर विधायक मनीष जायसवाल, क्षेत्रीय संयुक्त महासचिव सुनील सिन्हा, प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश नाथ दूबे, प्रांतीय महासचिव डॉ. दंपती कुमार सिंह, प्रांतीय संगठन मंत्री अंकित मोदी, प्रांतीय वित्त सचिव विनय कुमार पांडेय, प्रांतीय उपाध्यक्ष शैलेंद्र दत्त शुक्ल आदि ने संबोधित किया।

कहीं आप मिलावटी दाल का सेवन तो नहीं कर रहे

संतकबीरनगर (जीकेबी)। खाने में अरहर दाल का खूब इस्तेमाल होता है। लोग दाल में तड़का लगाकर खाना खूब पसंद करते हैं। लेकिन जो दाल आप खा रहे हैं कहीं इसमें मिलावट तो नहीं। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से आ रही दाल में खेसारी की मिलावट करके बेचा जा रहा है। खेसारी मिलावट की दाल लोगों की सेहत पर असर डाल रहा है। इसे लगातार खाने से आंख की समस्या और लकवा मारने का खतरा रहता है। खाद्य विभाग की टीम ने दो माह में दाल के चार नमूने लिए जो जांच के लिए लैब भेजे गए है। शहर के प्रमुख व्यापारियों की माने तो मिल से जो दाल निकलती है उसका आकार एक बराबर होता है। अगर उसमें खेसारी की मिलावट कर दी जाए तो फर्क पता चल जाएगा। व्यापारियों का कहना है कि अगर आप दाल खरीद रहे हैं तो उसे बारीकी से देख लें। जो लोग दाल मंगाते हैं तो उसे अच्छी तरह से जांच परख लेते हैं। शहर में कुछ जगहों पर पटरी पर तरह-तरह के रंग-बिरंगे दाल बेचे जा रहे हैं, जिसमें खेसारी की मात्रा अधिक होती है। व्यापारियों का कहना है कि जो दाल आ रही है वह गोरखपुर मंडी से ही मंगाया जाता है। मंडी में छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से दाल आती है। वहां भी सतर्कता बरती जा रही है, पर मिलावटखोर दाल में खेसारी

एक क्विंटल में दो हजार का मुनाफा

संतकबीरनगर। एक क्विंटल दाल में खेसारी मिलाने से करीब दो हजार का मुनाफा मिलावटखोर कमाते हैं और शुद्ध दाल की कीमत पर बेच देते हैं। जिले में रोजाना करीब 20 क्विंटल दाल की खपत है। यह दाल अन्य दाल से करीब 15 रुपये सस्ती होती है और शहर के किसी भी फुटपाथ पर मिल जाएगी।

बोले जिम्मेदार

मिलावटी दाल को लेकर सतर्कता बरती जाती है। ज्यादातर दाल गोरखपुर मंडी से आती है। वहां पर भी छत्तीसगढ़ से दाल आती है। गोरखपुर के व्यापारी सतर्कता बरत रहे हैं। यह कहा गया है कि दाल खरीदते समय उसकी गुणवत्ता देख लें, अगर मिलावटी है तो उसका भुगतान न करें। वैसे अभी तक इस मामले में किसी व्यापारी की शिकायत नहीं आई है।

- सर्वदानंद पांडेय, अध्यक्ष, पूर्वांचल उद्योग व्यापार मंडल

दो माह में दाल के चार नमूने लिए गए थे। इसमे से दो नमूने तो सही मिले पर दो नमूने के रिपोर्ट अभी तक नहीं आए है, इसमे कुछ गडबडी है, नमूना की रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वैसे टीम लगातार दाम व अन्य खाद्य सामग्री की जांच करती रहती है। **- जेपी तिवारी, मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी**

बच्चों का धर्मांतरण कराने की पिता ने जताई आशंका, पुलिस कर रही जांच

तमकुहीरोड (कुशीनगर)। सेवरही थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने पत्नी और रिश्तेदारों पर बच्चों के धर्मांतरण कराने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने इस मामले में सेवरही पुलिस को तहरीर देकर बताया है कि पत्नी उसके बच्चों का खतना कराना चाहती है। बच्चों को लेकर वह 16 मई से ही गायब है। इस मामले में पति ने कार्रवाई की मांग की है। तहरीर के आधार पर पुलिस युवती के परिवार के तीन सदस्यों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।

सेवरही थाना क्षेत्र के एक गांव के युवक ने उसी गांव की एक दूसरे धर्म की युवती से साल 2016 में शादी की थी। वह दबाव में आकर 2020 में दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया। युवक के इस कदम का परिवार व समाज में जब विरोध होने लगा तो मामला सेवरही थाने तक पहुंचा। युवक ने फिर अपरा मूल धर्म अपना लिया। उसके बाद पति-पत्नी राजी-खुशी रहने लगे। युवक और युवती से छह साल का पुत्र और चार साल की बेटी है। दोबारा यह मामला तब तूल पकड़ने लगा, जब मायके वालों ने फोन कर बच्चों का खतना कराने की बात कही। इसी बात को लेकर दोनों में तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी। युवक पत्नी को ऐसा करने से बार-बार मना करने लगा। लेकिन बात नहीं बनी। युवक का आरोप है कि वह 16 मई को टेंपो लेकर बाहर गया तो उसकी पत्नी बच्चों को लेकर रिश्तेदार के साथ गायब हो गई। दोपहर बाद युवक घर पहुंचा तो इसकी जानकारी हुई। इसके बाद उसने सभी जगहों पर पत्नी व बच्चों की तलाश की, लेकिन कहीं भी पता नहीं चल सका। युवक ने आशंका जताई है कि उसकी पत्नी उसके बच्चों का खतना करा देगी। धर्मांतरण की आशंका जताते हुए सेवरही पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। मामला संज्ञान में आने के बाद पुलिस हर बिंदुओं पर जांच कर रही है।

बताया जा रहा है कि युवती के परिवार के तीन सदस्यों को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। इस संबंध में एसएचओ दिग्विजय नारायण राय ने बताया कि तहरीर के आधार पर पुलिस कई बिंदुओं पर जांच कर रही है।

सड़क पर शव रखकर किया प्रदर्शन

पिपरा बाजार (कुशीनगर)। नेबुआ नौरंगिया थाना क्षेत्र के बलकुड़िया गांव निवासी साइकिल सवार की रविवार को रोलर के नीचे दबकर मौके पर ही मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के लिए शव गांव पहुंचा तो मुआवजे की मांग को लेकर गांव वालों ने सोमवार को सड़क जाम कर दी। शव को सड़क पर रखकर गांव के लोग प्रदर्शन करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों को समझा-बुझाकर शांत कराया। इसके बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। गांव वालों के विरोध प्रदर्शन से करीब दो घंटे तक पडरौना-बलकुड़िया मार्ग पर आवागमन बाधित रहा। थाना क्षेत्र के बलकुड़िया गांव निवासी अंगद यादव (47) जिला मुख्यालय के एक स्कूल में काम करते थे। वे रविवार को सुबह करीब 10 बजे स्कूल जा रहे थे। तभी अकबरपुर गांव के बड़वा छापर के समीप सड़क निर्माण के दौरान रोलर के नीचे दब गए। इससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों व स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद निमार्णाधीन सड़क पर काम करने वाले मजदूर रोलर लेकर वहां से भाग निकले। पोस्टमार्टम के लिए जब शव गांव पहुंचा तो गांव वालों ने मुआवजा की मांग को लेकर सोमवार की सुबह करीब आठ बजे पडरौना-बलकुड़िया मार्ग को जाम कर दिया। गांव वालों का कहना है कि अंगद यादव का परिवार गरीब है। उनकी मौत से परिवार पर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा है।

ऐसे में उसे मुआवजा दिया जाए। सड़क जाम की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे इंस्पेक्टर हर्षवर्धन सिंह ने नाराज गांव वालों को समझा-बुझाकर उन्हें शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। करीब दो घंटे बाद परिजन व गांव के लोग मान गए और शव के अंतिम संस्कार के लिए राजी हो गए। इंस्पेक्टर हर्षवर्धन सिंह ने बताया कि पीड़ित पक्ष की तरफ से अब तक तहरीर नहीं दी गई है। तहरीर मिलने के बाद मामले में कार्रवाई की जाएगी।

पूरे देश की नजर और सियासी सरगर्मी गोरखपुर लोकसभा सीट पर

गोरखपुर (जीकेबी)। संसदीय चुनावी आंकड़ों पर गौर करें तो तो यह पाते हैं कि वर्ष 1984 तक हुए आठ चुनावों के दरम्यान यहां छह बार कांग्रेस का दबदबा रहा। इस बीच सिर्फ दो बार कांग्रेस को यह सीट गंवानी पड़ी थी। 1967 में गोरक्षपीठ के तत्कालीन महंत दिग्विजयनाथ से और 1977 में इमरजेंसी के विरोध की लहर में जनता पार्टी के प्रत्याशी हरिकेश बहादुर से।

वर्ष 1984 के चुनाव में सफलता हासिल करने के बाद से ही इस संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस पहले जीत को तरसती रही और उसके बाद जमानत बचाने तक के लिए। पिछली सदी के अंतिम दशक से गोरखपुर की सीट पर. गोरक्षपीठ का दबदबा बना, जो अब तक कायम है। वर्ष 1989 से लेकर 1996 तक तीन चुनावों में तत्कालीन गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ और 1998 से लेकर 2014 तक पांच चुनाव में वर्तमान पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ को जनता ने संसद के लिए अपना प्रतिनिधि चुना। इसके पूर्व 1967 में तत्कालीन महंत दिग्विजयनाथ और 1969 में उनके ब्रह्मलीन होने के बाद महंत आवेदन हाथ गोरखपुर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। राम मंदिर आंदोलन के दौरान 1989 के चुनाव में महंत हुए दिनांक में दोबारा राजनीति में वापसी के और उसके बाद फिर गोरखपुर लोकसभा क्षेत्र पर गोरखपुर सीट के दौड़वे का सिलसिला चल पड़ा। कुंडेश्वर 89 का चुनाव महंत आवेदन में हिंदू महासभा के प्रत्याशी के रूप में लड़ा था उसके बाद वह और कैसे सहयोगी आदित्यनाथ लगातार भाई करके दिग्गज नेताओं की कतार में शामिल होकर लड़ते और जीत हासिल करते रहे। पीछे दो लोकसभा चुनाव की यदि चर्चा की जाए तो गोरखपुर में बस्ती मंडल की सभी 9 सीटों पर पीठ के आभामंडल से भाजपा के प्रत्याशियों को जिताते रहे हैं इस क्षेत्र को भगवा खेलने का घर बनाने का श्रेय नाथ पीठ को ही जाता है । योगी आदित्यनाथ के 2017 में मु ख्यमंत्री बनने के बाद गोरखपुर का चेहरा भले ही संसदीय सीट पर नहीं दिखता है लेकिन 1 वर्ष के उपचुनाव वाले कार्यकाल को हटा दे तो 2019 से वर्तमान सांसद रवि किशन खुद को रक्षक का सेवक और पीठ का खड़ा हूं रखकर सेवा करने वाला बात कर लिया निश्चित नहीं करते कि वह योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में ही चुनाव लड़ रहे हैं।

गठबंधन प्रत्याशी वर्ष 2018 के उप चुनाव में जातीय समीकरण के माध्यम से सपा प्रत्याशी प्रवीण निषाद (वर्तमान में संत कबीर नगर से भाजपा प्रत्याशी) को मिली जीत को नजर प्रमणकर यदि एक बार फिर मंदिर की आभा में उदास है नजर आ रहे हैं भाग्य देश के 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के सारे समीकरण ध्वस्त हो गए और गोरखपुर की सीट पर भगवा का आधिपत्य स्थापित हो गया। इन्सर्ट : निषाद बहुल संसदीय क्षेत्र मानकर सपा गोरखपुर संसदीय सीट पर निषाद प्रत्याशियों के माध्यम से दोनों विभाजुमति रही है हालांकि आम चुनाव में यह हमेशा निष्प्रभावी ही सिद्ध हुआ। पिछली बार निषाद प्रत्याशी राम भुवाल के साथ को रवि किशन से मिला कर बिहार के बाद एक बार फिर सपा ने पुराने रणनीति अपनाते हुए अपना प्रत्याशी काजल निषाद को चुनाव मैदान में उतारा है सपा का यादव कितना सफल होगा इस पर संख्या इसलिए दिख रहा है कि निषाद बिरादरी के वोटो पर अधिकार बताने वाले निषाद पार्टी भाजपा की सहयोगी होने के कारण सांसद रवि किशन के साथ ही है उध र रवि किशन खुद कह रहे हैं कि यह मंदिर की सीट है और फिर मंदिर की ही रहेगी भाजपा और रवि किशन इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि नाथ-पिता के प्रति आस्था में हमेशा जातीय समीकरणों को ध्वस्त करने का काम किया है लिहाजा उनकी रणनीति उसी आस्था को आगे कर एक बार फिर इस सांसदीय सीट को अपने नाम पर रहने की है।

लोकतंत्र के उत्सव के संपन्न कराने के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय से खजनी विधान सभा क्षेत्र के मतदान से पूर्व सामग्री का मिलान करते मतदानकर्मी

उत्साहित मतदाताओं का हौसला बुलंदी पर

प्रचंड गर्मी भी मतदाताओं के जोश को ठंड न कर सकी

संवाददाता

गोरखपुर (जीकेबी)। बस्ती मंडल की तीनों संसदीय सीटों पर शनिवार को मतदान संपन्न हो गया। प्रचंड गर्मी के कारण कम मतदान की जो आशंका व्यक्त की जा रही थी, वह निर्मूल साबित हुई। लोगों ने जमकर मतदान किया और 2019 के

चुनाव के लगभग बराबर रहे। सुबह सात बजे से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई थी और मतदान कैंद्रों पर मतदाताओं के आने का सिलसिला भी शुरू हो गया। पहले यह लगा कि सुबह गर्मी कम होने के कारण यह स्थिति है धूप के साथ सन्नाट होगा लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता गया, कयासों का दौर खत्म होता गया। बढ़ती तपिश भी मतदाताओं का हौसला नहीं तोड़ पायी। दोपहर में भीषण गर्मी के बीच मतदान काम के आशंका गलत साबित होगी भी अधिकतर बूथों पर मतदाता नजर आए। शाम को छह बजे तक कई लोग लाइन में लगे रहे, उनका वोट डलवाकर ही मतदान संपन हुआ। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए तीनों जिलों में खास इंतजाम किए गए थे। मतदाताओं के घर पर्ची भेजी गई थी तो उन्हें निमंत्रण भी दिया गया था। मतदाता जागरूकता के अभियान भी चलाए गए थे। इसी का परिणाम था कि लोगों ने गर्मी की

चुनौती को स्वीकार करते हुए बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र से सुबह 9:00 बजे तक 14.55 प्रतिशत मतदान हुआ था लेकिन 2 घंटे बाद 14% की वृद्धि नजर आई इसके बाद दोपहर 1:00 बजे तक का आंकड़ा आया तो उसमें गर्मी में हिंदू घंटे में भी लगभग 10% मतदान हुआ या नहीं लगभग 2 लाख मतदाताओं ने इस बीच अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इटवा डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र ओके कुछ एक भूतों पर सन्नाटा था अन्य स्थानों पर स्थित ठीक नहीं दोपहर 3:00 बजे मतदान प्रतिशत 43.88 प्रतिशत हो गया इस दौरान सबसे मुश्किल 2 घंटे में लगभग 6% की वृद्धि हुई यानी 17000 से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और शाम 5:00 बजे तक आधे से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर चुके थे ऐसे ही स्थिति बस्ती में भी देखी गई जहां दोपहर में मतदान प्रतिशत थोड़ा सुस्ती के साथ चला लेकिन शाम तक अपने पूरे रवानी पर था।

महिलाओं ने किया शराब की दुकान खोलने का विरोध

गोरखपुर। गुलरिहा थाना क्षेत्र के जमुनिया गांव में सोमवार को स्कूल के पास बन रही देसी शराब की दुकान का स्थानीय महिलाओं ने विरोध किया। निर्माण कार्य रोकते हुए सड़क पर प्रदर्शन किया इनका कहना था कि स्कूल के पास कॉल नहीं दुकान से बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं का बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा गांव में दुकान का आवंटन करना गलत है इससे युवाओं पर गलत प्रभाव पड़ेगा। नेतृत्व कर रहे कमला शंकर मिश्रा ने बताया कि शराब दुकान स्कूल से कुछ ही दूरी पर खुल रही है महिलाओं के साथ ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि शराब की दुकान का आवंटन रद्द कर इस गांव के बाहर किया जाए का धूप कितनी तेज पड़ रही है कौन सदाबहार है।

गुटखा खाना छोड़ दो तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगी

प्रकरण-एक

रेलवे कॉलोनी में झारखंड के रहने वाले एक दंपती की शादी सात साल पहले हुई थी। पति रेलवे में कर्मचारी हैं। पति को गुटखा खाने की आदत है। वह गुटखा खाकर कहीं भी थूक देते हैं। इस कारण घर की फर्श खराब हो गई है। इसे लेकर कई बार लड़ाई हो चुकी है। इन्हें देखकर बेटा भी वहीं कर रहा है। वह भी गुटखे की तरह चॉकलेट खाता है और फिर घर में थूक देता है। बेटे की आदत न बिगड़े इसके लिए अब पति साथ नहीं रहना चाहती हूं। दोनों का मामला दो महीने पहले मार्च में मि. हला थाने में आया था। चार बार काउंसिलिंग करने के बाद भी बात नहीं बनी। अब दोनों का मामला न्यायालय में चला गया है।

प्रकरण-दो

खोराबार थाना क्षेत्र का युवक पत्नी के दो माह से मायके रहने की शिकायत लेकर दो सप्ताह पहले 12 मई को महिला थाना आया था। युवक का कहना था कि पत्नी ने उसे बच्चों से दूर कर दिया है। वह घर नहीं आना चाह रही है। पुलिस ने पति-पत्नी को बुलाकर जब समझाया तो पत्नी ने कहा कि पति खुद तो अनुशासनहीन रहते हैं, अब बच्चे को भी बिगाड़ रहे हैं।

इस बात को लेकर रोज घर में कलह होती थी।इसलिए घर छोड़ दी हूं। इनके सुधरने पर ही घर जांऊगी। पत्नी का कहना था कि पति कपड़े, जूते, बैग, फाइल को घर में बिखेरे रहते हैं। पान मसाला खाकर बाल्कनी में थूक देते हैं। हालांकि दो काउंसिलिंग के बाद पति ने अपनी आदतें सुध ारने का समय मांगा जिसके बाद बुधवार को महिला घर जाने के लिए राजी हो गई।

प्रकरण-3

गोरखनाथ थाना क्षेत्र निवासी सरकारी कर्मचारी के गुटखा खाने की आदत से परेशान पत्नी कुछ दिन पहले महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पत्नी का कहना है कि पति गुटखा खाकर कपड़े गंदे करते हैं। कपड़े साफ नहीं होने पर लड़ाई करते हैं। घर में गंदे मोजे और कपड़े फेक देते हैं।

इसे देखकर बच्चे भी घर को गंदा कर रहे हैं। दिन भर घर की सफाई करती रहती हूं। रोज शाम ड्यूटी से घर आने पर पति ताना मारते हैं कि तुम कुछ काम नहीं करती हो। इस कारण परेशान होकर छह महीने से मायके रह रही हूं। अब घर तभी जाऊंगी जब पति गुटखा खाना छोड़ेंगे।

गोरखपुर(जीकेबी)। महिला थाने में पति-पत्नी के बीच शक, शराब और घरेलू विवाद के मामले आते रहते हैं। अब कुछ ऐसे भी मामले आ रहे, जिसमें महिला थाने की पुलिस भी परेशान है कि आखिर वह इसे सुलझाने के लिए क्या करें। पत्नियां शिकायत लेकर थाने पहुंच रही हैं कि पति खुद तो अनुशासनहीन रहते हैं, बच्चों को भी यहीं सिखा रहे हैं।

कई लोगों की पत्नियां तो इन आदतों तंग आकर मायके चली गईं। उनका कहना है कि पति पहले गुटखा खाना छोड़ें तभी ससुराल जाऊंगी।

दरअसल इन दिनों कुछ पत्नियां पति के गुटखा खाकर घर में थूकने, कूड़ा और घर का सामान फैलाने की आदत से परेशान हैं। इसकी शिकायत लेकर वह महिला थाने पहुंच रही हैं। उनका कहना है कि पति ऑफिस की तरह घ र पर भी कहीं भी गुटखा खाकर थूक देते हैं, जिससे दीवारों पर दाग पड़ जाते हैं। जिसे छुड़ाने में काफी समय बर्बाद होता है। इसके साथ ही वह केले के छिलके, तकिए, कपड़े, जूते को इधर-उधर फैला देते हैं। अब तक पति गंदगी फैलाते थे तो पत्नी किसी तरह साफ करती थीं, लेकिन अब वह बच्चों को भी बेपरवाह बना रहे हैं। बच्चों को सफाई से रहने की सीख नहीं देते। पति की आदतों का अनुसरण कर बच्चे भी घर में इधर-उधर कूड़े फैला रहे हैं।

इस कारण रोज घर में लड़ाई होती है। पत्नियां पति की इन आदतों से परेशान होकर महिला थाने में गुहार लगा रही हैं...मैडम पति की आदतों से परेशान हो चुकी हूं। अब साथ तभी रह सकती जब यह सुधर जाएं।

वहीं पतियों का कहना है कि कुछ आदतें हमेशा साथ रहती हैं। ये हमेशा हर चीज के लिए डांटती हैं। गुटखा खाना कैसे छोड़ सकता हूं।

इन्हें ज्यादा सफाई करने की आदत है। इस कारण रोज लड़ाई होती है।

महिला थाने में पति-पत्नी विवाद के कुछ ऐसे मामले आते रहते हैं, जिनका हल निकालना मुश्किल होता है। फिर भी उन्हें समझाकर साथ रहने की सलाह दी जाती है। इसके लिए कई बार पति-पत्नी को बुलाकर उनकी काउंसिलिंग कराई जाती है। पुनः घर बसाने का पूरा प्रयास किया जाता है, पर ऐसे मामलों में दोनों को अपनी कुछ आदतों को बदलने की पुलिस सलाह देती है। अधिकांश मामले में दोनों साथ रहने को तैयार हो जाते हैं।

- राजकुमारी शुक्ला,
उप निरीक्षक, महिला थाना

गोरखपुर में गर्मी का प्रचंड रूप

जातीय मतों को सहेजने की तैयारी में भाजपा और सपा

सिद्धार्थनगर ब्राह्मण 14 प्रतिशत, पिछड़ी 25 प्रतिशत, दलित 18 प्रतिशत, मुस्लिम 30 प्रतिशत। डुमरियागंज लोकसभा सीट पर जातियों की यह संभावित संख्या वहां के समीकरणों की और स्पष्ट संकेत करती है। विकास से शुरू हुई बात अब पूरी तरह से जातियों के चक्रव्यूह में उलझती जा रही है।

विकास से शुरू हुई बात अब पूरी तरह से जातियों के चक्रव्यूह में उलझती जा रही है।

ऐसा नहीं है कि कोई एक दल इसपर फोकस कर रहा है। यहाँ भाजपा व सपा के बीच सीधी लड़ाई के आसार हैं। सपा ने अपने मुस्लिम एवं यादव वोट बैंक के साथ पूर्वांचल के कदावर ब्राह्मण परिवार से प्रत्याशी को उतारकर लड़ाई को रोचक बना दिया है। ब्राह्मणों को अपना परंपरागत वोट मानने वाली भाजपा भी सावधान है और अपने ब्राह्मण चेहरों को यहां लाकर अपने पक्ष में माहौल बनाने में जुटी है। इसके साथ ही अन्य पिछड़ी जातियों व दलित मतदाताओं को साधने के लिए भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। भाजपा ब्राह्मण मतों को साधने के लिए यह दो बार डिप्टी सीएम बृजेश पाठक की सभा कर चुकी है। क्या हुआ राम मंदिर मेडिकल कॉलेज पासपोर्ट ऑफिस केंद्रीय विश्वविद्यालय विपश्यना केंद्र सहित विभिन्न परियोजनाओं की चर्चा करने के साथ ही जाति के मतों को साधने पर जोर दे रहे हैं।

प्रदेश के राज्य मंत्री रजनी तिवारी पिछले दो दिनों से जिले में ही काम कर रही है 2 दिन में उनकी जिले में 6 सभाएं हो चुकी हैं इसके अतिरिक्त जनसंपर्क के जरिए भाजपा के पक्ष में माहौल बना रही हैं। 8 मई को देवरिया सांसद रमापति राम त्रिपाठी जिले में भूत सम्म. 17 में को सूरतगढ़ में अपना तलाश की राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की जनसभा को आयोजित करके कुर्मी बातों को सहेजने पर भी बोल दिया गया। इस चुनाव में सपा ने प्रत्याशी के रूप में संत कबीर नगर के पूर्व अध्यक्ष कुशल तिवारी को उतार का ब्राह्मण मतों को कर लगाने की कोशिश की है सपा के लोगों का मानना है कि करीब 80% मुस्लिम उनके साथ ही रहते हैं। यादव बेस वोटर है। ब्राह्मण प्रत्याशी के जरिए ब्राह्मण मतदाताओं का समर्थन मिला तो करें तीन से चार लाख मतों पर उनकी पकड़ हो जाएगी इसके अतिरिक्त अन्य जातियों के मतों को सहेली ने पर भी काम चल रहा है यहां तो स्थितियां बदल सकती है।

लन कर चुके हैं इसके अलावा भी ब्राह्मण शेरों को आगे करके भाजपा प्रत्याशी लोगों को यह संदेश देने में लगे हैं कि इस वर्ग की असली हिमायती भाजपा ही है। संसदीय सीट पर करीब 6 से 7% मतदाता निषाद समुदाय के हैं ऐसे में बीजेपी इन बातों को भी अपने साथ में रखना चाहती है इसके लिए जिले में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन कराया जा चुका है। शनिवार को भाजपा मैं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों कैबिनेट मंत्री डॉ संजय निषाद की जनसभा भी कराई इसके साथ विधानसभा में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण भी थे इनके जरिए दलित मतदाताओं को संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि उनके हित सिर्फ भाजपा में ही सुरक्षित है। 2 दिन पहले राज्यसभा सदस्य वह पूर्व डीजीपी बृजलाल की डुमरियागंज में सज्जन सभा कराई गई जो इसी संसदीय सीट के मूल निवासी हैं।

वक्तव्यों के संदेशों का अर्थ समझती है जनता

प्रधानमंत्री ने अडानी और अंबानी का नाम लेकर आरोप भले ही राहुल गांधी पर लगा दिया हो लेकिन इससे जनता मैं जो संदेश गया वह तो राहुल के बजाय प्रधानमंत्री पर ही उल्टे पड़ गया है क्योंकि जरूरी यह नहीं है कि क्या कहा जा रहा है जो कहा जा रहा है उसके पीछे क्या छिपा है जनता तो उसका अर्थ निकालती है इससे यही लगता है कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ दल का आत्मविश्वास डिग रहा है इसके कारण वी अंधेरे में हर तीर को चुनाव में आजमाना चाह रही है भले ही कुछ तीर उल्टे उसे ही क्यों न लग जाएं ।

तेलंगाना के करीमनगर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उद्योगपति अडानी और अंबानी से सौदा कर लिया है इसीलिए वह अब इनका नाम चुनाव में नहीं ले रहे हैं क्योंकि टेंपो में भर भर कर माल मार लिया है। उन्होंने कहा कांग्रेस के शहजादे (राहुल गांधी) पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे अंबानी अडानी लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है उन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं कि शहजादे घोषित करें कि चुनाव में अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है? काले धन के कितने बोरे भरकर मारे हैं। क्या सौदा हुआ है? रातों रात अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों-रात गलियां बंद हो गई मतलब कोई ना कोई चोरी का माल टेंपो भरकर आपने पाया है देश को जवाब देना पड़ेगा।

इसके पीछे कारण यह रहा है कि देश के अंदर बंदरगाह से लेकर हवाई अड्डे और अन्य सार्वजनिक संपत्तियां इनके पास आ गई है और इनका व्यापार लाखों गुना तेजी से पिछले 10 सालों में बढा है। यही नहीं जब कोरोना कल में लोग 2 जून के खाने के लिए तरस रहे थे दानदाताओं स्वयंसेवी संगठनों और सरकार के कुछ संस्थाओं के माध्यम से बंटने वाले फ्री भोजन को पाने के लिए लालायित रहते थे उसमें भी कभी एक परिवार के पांच लोगों में से तीन को भोजन मिल पाता था दो को उसी में से अपना गुजारा करना पड़ रहा था उन दिनों अंबानी और अडानी के ऊपर लक्ष्मी की कृपा बरस रही थी और ऐसा लग रहा था कि ऊपर वाला छप्पर नहीं आसमान फाड़ कर दे रहा है। देश में अर्थव्यवस्था ठप थी और इन दोनों उद्योगपतियों का नाम दुनिया के टॉप 15 उद्योगपतियों में गिना जाने लगा था। यही नहीं पहले और दूसरे नंबर की हॉल भी चल रही थी जब अडानी से पूछा कि ऐसा कैसे हो रहा है तो उन्होंने ऊपर वाले और अपनी मेहनत को इसका श्रेय दिया। राहुल गांधी ने खुलकर अडानी और अंबानी का मुद्दा और प्रधानमंत्री के संबंधों का आरोप सड़क से लेकर संसद तक लगाया चुनाव के दौरान भी उन्होंने इसका उल्लेख किया लेकिन प्रधानमंत्री का अडानी और अंबानी को लेकर जो आप राहुल गांधी पर लगाए गए उस हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गई है। अडानी सीजर एक साक्षात्कार में यह पूछा गया कि सारे महत्वपूर्ण टेंडर आपको ही क्यों मिलते हैं तो उनका कहना था कि हमें कोई अलग से फेवर नहीं दिया गया बल्कि हमारी कंपनियां गुणवत्ता मानकों का पालन करती है इसलिए हमें यह सब हासिल होता है। प्रधानमंत्री का भाषण सुनकर सभी लोग आश्चर्य में पड़ गए क्योंकि अडानी और अंबानी को प्रश्रय देने और देश भेज देने का आरोप कांग्रेस नेता राहुल गांधी खुलकर लग रहे हैं वह यह भी कहते हैं कि देश को इन्हीं के हाथों बेच दिया है ऐसे में प्रधानमंत्री का यह कथन लोगों में कुतूहल पैदा करता है कि अडानी और अंबानी दोनों ही नरेंद्र मोदी के खास उद्योगपति माने जाते हैं जिनसे सीधा संबंध बताया जाता है।

राजनीतिक हस्तक्षेप से त्रस्त शिक्षा संस्थान

विश्वविद्यालय शैक्षणिक सुधारों के बजाय राजनीतिक हितों के पोषण का केंद्र न बनने पाएं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति केंद्र सरकार और राज्यों के विश्वविद्यालयों में राज्य सरकारें करती हैं। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, वह अपने चहेतों को कुलपति नियुक्त करती है। हर राज्य में इस तरह के उदाहरण हैं। यदि कुलपति की नियुक्ति इस आधार पर होगी कि वह सत्तारूढ़ दल या उसके मुखिया का कितना करीबी है तो क्या उससे शैक्षणिक सुधार लाने की उम्मीद बेमानी नहीं होगी? कहने की जरूरत नहीं कि नियुक्तियां योग्यता और प्रतिभा के आधार पर होनी चाहिए, न कि राजनीतिक पसंद के आधार पर। विश्वविद्यालय मेधाओं का निर्माण करते हैं। यदि राजनीतिक विचारधारा के कारण मेधाओं की उपेक्षा होगी तो उसके घातक परिणाम होंगे।

भारतीय उच्च शिक्षा, जो कभी बौद्धिक स्वतंत्रता का प्रतीक थी, राजनीतिक हस्तक्षेप के बढ़ते खतरे का सामना कर रही है। यह हस्तक्षेप अकादमिक उत्कृष्टता की नींव – स्वायत्तता और स्वतंत्रता को कमजोर करता है और अनुसंधान, शिक्षण और छात्र चर्चा पर भयावह प्रभाव डालता है। राजनीतिक हस्तक्षेप से त्रस्त शिक्षा संस्थान, विश्वविद्यालयों में नियुक्तियां योग्यता और प्रतिभा के आधार पर होनी चाहिए, केंद्र और राज्य सरकारों को इस लक्ष्य को हासिल करने का उपक्रम करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले और शिक्षा संस्थान राजनीति हस्तक्षेप से मुक्त हों। उन्हें राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाना चाहिए। विश्वविद्यालय शैक्षणिक सुधारों के बजाय राजनीतिक हितों के पोषण का केंद्र न बनने पाएं।केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति केंद्र सरकार और राज्यों के विश्वविद्यालयों में राज्य सरकारें करती हैं। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, वह अपने चहेतों को कुलपति नियुक्त करती है। हर राज्य में इस तरह के उदाहरण हैं।

पाठ्यचर्या संबंधी निर्णय राजनीतिक लक्ष्यों से प्रभावित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, विशेष राष्ट्रीय आख्यानों को आगे बढ़ाने या संवेदनशील विषयों पर सेंसर वार्ता को आगे बढ़ाने की पहल की गई है। यह आलोचनात्मक सोच के साथ-साथ व्यापक शिक्षा को भी बाधित करता है। यदि संकाय और छात्र अलग-अलग राय व्यक्त करने के नकारात्मक परिणामों से डरते हैं तो वे राजनीतिक दबाव के कारण आत्म-सेंसर कर सकते हैं। यह ईमानदार चर्चा और परेशान करने वाली सच्चाइयों की खोज को रोकता है। विडंबना है कि शिक्षा के तमाम पाठ्यक्रम, जिन्हें अब कार्यक्रम कहा जा रहा है, पुराने ढर्रे के हैं। कोई भी शैक्षणिक सुधार पाठ्यक्रम को एकांगी होने के दोष से बचाकर, उच्च शिक्षा तथा शोध का मान उन्नत करके ही संभव है। शोध का मान तब उन्नत होगा, जब गंभीर शोध और सतत अध्ययन का रचनात्मक परिवेश निर्मित हो। यह परिवेश निर्मित कर ही युवा शक्ति को सकारात्मक और सृजनशील ढंग से ऊर्जस्वित किया जा सकता है, पर त्रासदी है कि उच्च शिक्षा की विषय वस्तु और प्रक्रिया प्रायः विदेशी ज्ञान को मानक मानकर की जाती रही है, जिसके परिणामस्वरूप हम अपनी परंपरा से कटकर दूर चले गए हैं।

राजनीतिक कारक अनुसंधान निधि और प्रोफेसर पदों के वितरण पर प्रभाव डाल सकते हैं। यह योग्यता को नष्ट करता है और संभावित विवादास्पद अनुसंधान को रोकता है। राजनीतिक हस्तक्षेप से विश्वविद्यालयों की स्वशासन की क्षमता कमजोर हो सकती है। इससे सर्वोत्तम उम्मीदवारों को नियुक्त करने और अपने स्वयं के शैक्षणिक लक्ष्य स्थापित करने की उनकी क्षमता सीमित हो जाती है। विश्वविद्यालयों ने कभी-कभी प्रशासनिक पदों पर राजनीतिक रूप से संबद्ध व्यक्तियों की नियुक्ति देखी है, जिससे निर्णय लेने में संभावित पूर्वाग्रह के बारे में चिंताएं बढ़ गई हैं। यदि कुलपति की नियुक्ति इस आधार पर होगी कि वह सत्तारूढ़ दल या उसके मुखिया का कितना करीबी है तो क्या उससे शैक्षणिक सुधार लाने की उम्मीद बेमानी नहीं होगी? कहने की जरूरत नहीं कि नियुक्तियां योग्यता और प्रतिभा के आधार पर होनी चाहिए, न कि राजनीतिक पसंद के आधार पर। विश्वविद्यालय मेधाओं का निर्माण करते हैं। यदि राजनीतिक विचारधारा के कारण मेधाओं की उपेक्षा होगी तो उसके घातक परिणाम होंगे।

यह विशेष रूप से सामाजिक विज्ञान और मानविकी में देखा जाता है, जहां वरिष्ठ शिक्षाविद भी उस काम को प्रकाशित करने से डरते हैं जिसके बारे में उन्हें लगता है कि इससे राज्य के अधिकारियों से उनके लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, प्रताप भानु मेहता और समीना दलवई जैसे बुद्धिजीवी।सरकारी नीतियों के खिलाफ शांतिपूर्ण छात्र विरोध प्रदर्शनों को कभी-कभी भारी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है, परिसर में मुक्त भाषण और असहमति को रोक दिया जाता है। उदाहरण के लिए, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज (टीआईएसएस) और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में। कुछ मामलों में, सरकारों ने राजनीतिक रूप से असुविधाजनक समझी जाने वाली पुस्तकों या विषयों को पाठ्यक्रम से हटाने का प्रयास किया है। प्रायः देखा जाता है कि राजनीतिक पसंद-नापसंद के आधार पर सरकारें विश्वविद्यालयों को धन आवंटित करती हैं। राज्याश्रित होने के कारण विश्वविद्यालयों को राजनीतिक दबाव का सामना करना पड़ता है। राज्यों के विश्वविद्यालय संसाधन की कमी के कारण समस्याग्रस्त रहते हैं और सरकार के मुखापेक्षी बने रहते हैं। प्राचीन काल में शिक्षा राज्याश्रित नहीं थी। इसीलिए तब गुरु की स्वतंत्र सत्ता होती थी। तब शिष्यों को नैतिक और बौद्धिक रूप से गुरु गढ़ता था और शिष्य के व्यक्तित्व के निर्माण को अपना धर्म मानता था। आज की शिक्षा न दुराग्रहों से मुक्त है, न राजनीतिक बाधाओं से। आज की शिक्षा समावेशी भी नहीं है। आज तक न तो एकसमान पाठ्यक्रम लागू हो पाया, न एकसमान शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई गई। भारत राजनीतिक हस्तक्षेप के जोखिमों को समझकर और सक्रिय उपायों को लागू करके यह गारंटी दे सकता है कि उसकी उच्च शिक्षा प्रणाली बौद्धिक जांच और आलोचनात्मक विचार के लिए एक वास्तविक स्थान बनी रहेगी, जो एक समृद्ध लोकतंत्र और टिकाऊ भविष्य के लिए आवश्यक है। आज अभिभावक अपनी संतान को इस तरह की शिक्षा दिलाते हैं जिनसे करियर बने और यथेष्ठ धनोपार्जन हो। आदर्श स्थिति यह है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, जो विद्यार्थी को बेहतर मनुष्य बनाए। बेहतर मनुष्य ही बेहतर नागरिक होगा, जिसके लिए देश और देशहित सर्वोपरि होगा। केंद्र और राज्य सरकारों को इस लक्ष्य को हासिल करने का उपक्रम करना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मिले और शिक्षा संस्थान राजनीति हस्तक्षेप से मुक्त हों। उन्हें राजनीति का अखाड़ा नहीं बनने दिया जाना चाहिए।

विश्वविद्यालय शैक्षणिक सुधारों के बजाय राजनीतिक हितों के पोषण का केंद्र न बनने पाएं। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्ति केंद्र सरकार और राज्यों के विश्वविद्यालयों में राज्य सरकारें करती हैं। जिस राज्य में जिस पार्टी की सरकार होती है, वह अपने चहेतों को कुलपति नियुक्त करती है। हर राज्य में इस तरह के उदाहरण हैं। यदि कुलपति की नियुक्ति इस आधार पर होगी कि वह सत्तारूढ़ दल या उसके मुखिया का कितना करीबी है तो क्या उससे शैक्षणिक सुधार लाने की उम्मीद बेमानी नहीं होगी? कहने की जरूरत नहीं कि नियुक्तियां योग्यता और प्रतिभा के आधार पर होनी चाहिए, न कि राजनीतिक पसंद के आधार पर। विश्वविद्यालय मेधाओं का निर्माण करते हैं। यदि राजनीतिक विचारधारा के कारण मेधाओं की उपेक्षा होगी तो उसके घातक परिणाम होंगे।

–प्रियंका सौरभ

मुसलमानों को लेकर मोदीफोबिया झूठा या सच्चा?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। सबका साथ-सबका विकास और सबका विश्वास की टर्म के साथ मोदी अपने चुनावी अभियान में नजर आते हैं। वर्तमान राजनीति में मोदी जब भी अल्पसंख्यकों का जिक्र करते हैं तो अक्सर विपक्ष इसे मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित करने में जुट जाता है। बीजेपी और मोदी इस पर अपनी कितनी भी बातें कहें, लेकिन यहाँ भी मामला सिफर ही ठहरता है। हाल ही में मोदी ने अपने एक इंटरव्यू में कहा- मोदी मुसलमानों से अपने प्रेम का प्रचार नहीं करता है, विकास की बात करता है। इसके पहले भी पीएम मोदी के द्वारा- पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के श्देश के संसाधनों पर पहला अधिकार, मुसलमानों का हैश ; इस बयान के बाद सियासी पारे में बढ़ोत्तरी हुई थी। इस वक्त मोदी अपने चुनावी अभियान में- धार्मिक आधार पर कांग्रेस शासित राज्य सरकारों के द्वारा दिए जाने वाले आरक्षण के खिलाफ लगातार हमला बोल रहे हैं। पीएम मोदी लगातार कह रहे हैं कि- वे एसटी/एससी/ओबीसी का आरक्षण किसी हाल में खत्म नहीं होने देंगे। विपक्ष मोदी के इस बयान को भी मुस्लिम विरोध से जोड़ रहा है। अब फ्लैश बैक सहारे तथ्यों की पड़ताल करते हैं....और देखते हैं कि मोदी को लेकर चलने वाले मोदीफोबिया की हकीकत और फसाना क्या है? 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के एक साल बाद ही वर्ष 2015 में असहिष्णुता और कट्टरता बढ़ने का आरोप लगाया जाने लगा...। मोदी को घेरने के लिए अवार्ड वापसी अभियान चलाया गया....लेकिन इसके ठीक 2 वर्ष बाद 2017 में मोदी ने- मिशन यूपी को 312 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत से जीत लिया। यूपी के 2017 के इलेक्शन में बीजेपी मुस्लिम बहुल मानी जाने वाली सीटें भी जीतने में सफल रही। इनमें प्रमुख रूप से- देवबंद, मुरादाबाद नगर, कांठ, रूदौली, थाना भवन जैसी विधानसभा सीटें रहीं। बीजेपी के द्वारा मुस्लिम बहुल इन सीटों के जीतने पर उस वक्त सियासी पंडितों ने माना कि- बीजेपी इन सीटों को मुस्लिमों के समर्थन के बिना नहीं जीत सकती थी।

आगे चलकर मोदी 2019 के लोकसभा चुनाव में भी दोबारा जीत कर आए और अपनी इस टर्म में मोदी ने कुछ समय बाद ही ताबड़तोड़ फैसले लेने चालू कर दिए। 30 जुलाई 2019 को मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने तीन तलाक पर कानून पारित कर दिया, और इसे असंवैध ानिक घोषित कर दिया। मोदी ने कहा था कि- सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को तीन तलाक से मुक्ति दिलाई जिससे उनके अधिकारों की रक्षा संभव हुई। जब मोदी सरकार ने तीन तलाक को लेकर कानून बनाया, उस वक्त भी विपक्ष ने उन्हें घेरा था। और तीन तलाक कानून के खिलाफ मुहिम तेज की थी। यह एक ऐसा मामला था जो 1980 के दशक में भी खासा चर्चित रहा। उस वक्त शाहबानो प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने पलट दिया था। राजीव गांधी सरकार में मंत्री रहे वर्तमान में केरल के राज्यपाल आरिफ मो. हम्मद खान ने सरकार के फैसले के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। 2019 में ही ठीक एक महीने बाद 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने अपना एक और ऐतिहासिक फैसला लिया और कश्मीर से धारा 370 और 35 ए को समाप्त कर दिया। जोकि 9 अगस्त 2019 को कानून बन गया। भारत की राजनीति में यह एक ऐसा लाइलाज मर्ज था जिसका उपचार असंभव माना जाता था। उस समय भी विपक्ष ने इसे मुस्लिम विरोधी बताने का प्रयास किया था। जबकि कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति का.... मुस्लिम विरोध से दूर-दूर तक लेना-देना नहीं था। धारा 370 को समाप्त करना एक ऐसा ऐतिहासिक कदम था जो काश्मीर से आतंकवाद, अलगाववाद खत्म करने और विकास की मु ख्यधारा में जोड़ने का काम किया। मोदी के दूसरे टर्म में ही फिर आती है एक और तारीख 9 नवम्बर 2019 की। इस दिन वर्षों से चल रहे श्रीरामजन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुनाया। इसी के साथ ही राममंदिर निर्माण के द्वार खुल गए। जब रामजन्मभूमि का फैसला आया, उस वक्त भी जमकर सियासी बवाल मचा था। लेकिन यह एक ऐसा मामला था जिस पर विपक्ष चाहकर भी ज्यादा दिन विरोध न कर सका.... और मोदी को वॉक ओवर मिलता हुआ दिखा। पीएम मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के शुरुआती समय से ही कई बड़े फैसले लेने लगे। उन्हीं फैसलों में से एक था... 2019 में लाया गया नागरिकता संशोधन कानून। इस कानून के द्वारा- पाकिस्तान, बंग्लादेश और अफगानिस्तान से धार्मिक आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए शरणार्थियों को नागरिकता देने का प्रावधान किया। इसमें हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, पारसी और ईसाई शामिल हैं। सीएए के आते ही भ्रामक रूप से यह प्रचार किया जाने लगा कि यह मुस्लिम विरोधी कानून है। इससे मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। इस आधार पर मोदी को घेरने की कवायद की जाती रही। दिल्ली के शाहीन बाग में पूरा अखाड़ा जमा लिया गया था। वहाँ से लगातार मोदी को गालियाँ दी जाती रहीं...और फिर मोदी विरोध का यह अभियान 2020 में... दिल्ली दंगों के तौर पर जाना गया। ये वो वक्त था जब अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रंप भारत दौरे पर थे। उस वक्त शाहीन बाग में हुए दंगे से सैकड़ों लोगों को अपनी जान से हाथ गवाँना पड़ा था। तमाम राजनीतिक विश्लेषकों ने माना कि- तत्कालीन समय में ट्रंप के दौरे के समय, शाहीन बाग के दंगों का होना। विश्व में भारत की छवि ध मिल करने का प्रकरण ही समझ आया। उस दौरान आईबी के अंकित शर्मा, हेड कांस्टेबल रतनलाल जैसे कुछ बहुचर्चित मामलों ने सबको झकझोर कर रख दिया था.... वहीं हेड कांस्टेबल दीपक दहिया के ऊपर दंगों के दौरान शाहरूख पठान नामक युवक ने बंदूक तान दी थी..जिस पर आगे चलकर अदालत ने उस पर आरोप भी तय किए थे। अब प्रश्न यही उठता है कि- क्या सीएए कानून को लेकर शाहीन बाग आंदोलन सही था ? क्या भारत के मुस्लिमों के हित सीएए के द्वारा किसी प्रकार से प्रभावित होते हैं? स्पष्ट रूप से सीएए कानून जब भारतीय नागरिकों के हितों को, नागरिकता को- किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करता है। तब ऐसे में दिल्ली के शाहीन बाग में वर्षों पहले जो कुछ हुआ था, क्या वह सही था? तिस पर भी सीएए को लेकर मोदी को मुस्लिम विरोधी साबित किया जाता रहा। ठीक इसी तरह 2022 में हैदराबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोदी ने श्पसमांदाश मुस्लिमों का जिक्र कर एक बार फिर से समूचे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। मुस्लिम आबादी के मुताबिक, मुस्लिम जनसंख्या का 85% हैं। मोदी ने पसमांदा को लेकर कई बार अपनी चिंताएं जताईं और इस व्यापक वर्ग के कल्याण लिए अपनी प्रतिबध्दता जताते रहे हैं। मुस्लिम समाज के बीच सामाजिक सुधारों की कवायद करते रहे हैं। वास्तव में पीएम मोदी ने पसमांदा मुस्लिमों के विकास पर जो चर्चा छेड़ी थी, उस पर देश भर में व्यापक बहस होनी थी । लेकिन इस पर जिस ढंग की डिबेट होनी थी वो नहीं हो पाई। प्रधानमंत्री मोदी जब मुस्लिम समाज के बीच सामाजिक सुधारों की बात करते हैं, उन्हें मुख्यधारा में शामिल करने की बात करते हैं ; तो अक्सर उन्हें मुस्लिम विरोधी ठहराए जाने का प्रयास किया जाता है। पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही जो निर्णय लिए उस आधार पर जो तथ्य सामने आते हैं। उससे क्या स्पष्ट होता है। यह तय करना आप पर छोड़ते हैं....लेकिन यह जरूर हुआ है कि मोदी ने श्नमाजवादी और समाजवादीश राजनीति के बीच अपनी एक अलग लकीर जरूर खींच दी है।

कृष्णमुरारी त्रिपाठी अटल

भारतीय मुसलमानों के लिए अमेरिकी चिन्ता की खतरनाक वास्तविकता

खबर है कि रिलीजियस मजहबी स्वतंत्रता की स्वयंभू व ठेकेदार बनी अमेरिकी सरकार भारत में मुसलमानों की स्थिति पर बडी चिन्तित है। वह चिन्तित इसलिए नहीं है कि भारत में मुस्लिम आबादी सर्वाधिक 43 प्रतिशत की दर से बढ चुकी है और भारतीय मुसलमानों की विभिन्न जिहादी गतिविधियों से यहां के अनेक राज्यों में बहुसंख्यक हिन्दू समाज त्राहि-त्राहि कर रहा है; अपितु वह 'न्यूयॉर्क टाइम्स' नामक एक अमेरिकी अखबार की उस रिपोर्ट को ले कर चिन्तित है, जिसमें यह कहा गया है कि "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत में 'धर्मनिरपेक्ष ढांचा और मजबूत लोकतंत्र कमजोर' हुआ है।"

मालूम हो कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने "अपने ही देश में अजनबी: मोदी के भारत में मुसलमान होना" शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, जिसमें दावा किया गया है कि भारत में मुस्लिम समाज पीड़ा और अलगाव से जूझ रहा है। वे अपने बच्चों को ऐसे देश में पालने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उनकी पह. चान पर सवाल उठा रहा है। इस अखबारी समाचार बनाम दुष्प्रचार पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका ने कहा है कि वह इस मामले पर भारत सहित दुनिया भर के देशों के साथ बातचीत कर रहा है, क्योंकि वह धार्मिक स्वतंत्रता के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्ध है। अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा है कि श्श्हम दुनिया भर में सभी के धर्म या विश्वास की स्वतंत्रता के अधिकार के लिए सार्वभौमिक सम्मान को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा के लिए गहराई से प्रतिबद्ध हैं।श्श मिलर ने आगे यह भी कहा है कि "हमने भारत समेत कई देशों के साथ धार्मिक समुदायों के लिए समान रिलीजियस व्यवहार के महत्व पर चर्चा की है।" यहां यह गौरतलब है कि 'न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट और उस पर अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया ऐसे समय पर आई है, जब भारतीय मुसलमानों की आबादी में सर्वाधि 43% की असामान्य वृद्धि दर्ज की गई है और सारा मुस्लिम समाज एकजुट हो कर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विरुद्ध संसदीय चुनाव को प्रभावित करने के लिए 'वोटिंग जिहाद' का संगठित अभियान चला रहा है। इससे पहले यह मजहबी समाज देश के कई राज्यों में अपनी संगठित शक्ति के बुते शासन-प्रशासन पर काबिज हो कर वहां से धार्मिक समाज के लोगों (हिन्दुओं) को विस्थापित होने को बाध्य कर चुका है और फिलवक्त अनेक राज्यों की सियासत को अपने हिसाब से संचालित करने की हैसियत प्रदर्शित कर रहा है। इतना ही नहीं, वह भारतीय संविधान से इत्तर 'मुस्लिम पर्सनल लॉ' के सहारे विशेषाधिकारों की मलाई चाभ रहा है और 'मुस्लिम वक्फ बोर्ड' की लाठी से सरकारी-गैरसरकारी भू-खण्डों पर कब्जा करते हुए लाखों हेक्टेयर भूमि का स्वामित्व हासिल कर सेना व रेलवे के बाद सबसे बडा भू-स्वामी बना हुआ है।

जगजाहिर है कि भारत में मुसलमानों की हालत व हैसियत जितनी अच्छी है, उतनी मुस्लिम देशों में भी नहीं है। जबकि पडोसी पाकिस्तान में हिन्दुओं की आबादी 90% से भी ज्यादा घट गई है और वहां वे इस्लामिक स्टेट-संरक्षित उत्पीडन का इस कदर शिकार होते रहे हैं कि उनके मानवाधिकारों की रक्षा के लिए भारत सरकार को उन्हें भारतीय नागरिकता प्रदान करने का कानून बनाना पडा है। बावजूद इसके, अमेरिकी मीडिया इण्डस्ट्री और फॉरेन मिनिस्ट्री को भारत में ही मुसलमान आपदग्रस्त दीख रहे हैं, तो यह उनका दृष्टि-दोष नहीं है, अपितु एक सुनियोजित षड्यंत्रकारी प्रपंच है, जिसके सूत्र-समीकरण उस अमेरिकी आयोग (यूएससीआईआरएफ) के हाथों में हैं, जिसने अभी हाल ही में अपनी वार्षिक रिपोर्ट जारी कर भारत को 'धार्मिक स्वतंत्रता का हननकर्ता' बताते हुए विशेष चिन्ता वाले देशों की सूची में शामिल कर रखा है। यूएससीआईआरएफ के लगभग सभी सदस्य रिलीजियस विस्तारवादी चर्च मिशनरियों से सम्बद्ध है, जबकि इस आयोग का गठन ही अमेरिका ने वे. टीकन-पोप के दबाव में 'इण्टरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट' नामक कानून बना कर उसी के तहत कायम किया हुआ है।

देखने-सुनने में तो यह अधिनियम दुनिया के सभी राष्ट्रों के भीतर वहां के नागरिकों की धार्मिक स्वतंत्रता, अर्थात किसी भी रिलीजन-मजहब अथवा धर्म को अपनाने-मानने की स्वतंत्रता को संरक्षित करने के बावत इसकी वकालत करता है; किन्तु वास्तविक व्यवहार में यह 'धर्म (सनातन) त्यागने व रिल. ोजन-मजहब अपनाने' का मार्ग प्रशस्त करता है और इस हेतु चर्च-मिशनरी-संस्थाओं (एनजीओ) को सरंक्षित करता है। यही कारण है कि इस अमेरिकी अधिनियम के वैश्विक क्रियान्वयन की निगरानी करने वाला वह आयोग (यूएससीआईआरएफ) भारत में कायम धर्मान्तरण-रोधी कानूनों और विदेशी धन से संपोषित मिशनरी संस्थाओं को नियंत्रित करने वाले भारतीय कानूनों पर आपत्ति जताते रहता है, जैसा कि उसकी रिपोर्ट में कहा गया है कि- "बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार ने भेदभावपूर्ण राष्ट्रवादी नीतियों को मजबूत किया, घृणास्पद बयानबाजी को बढ़ावा दिया और सांप्रदायिक हिंसा को नियंत्रित करने में विफल रही, जिससे मुस्लिम, ईसाई, सिख, दलित, यहूदी और आदिवासी असमान रूप से प्रभावित हुए। गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधि नियम (यूएपीए), विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) एवं धर्मांतरण व गोहत्या विरोधी कान. ूनों के लगातार लागू होते रहने के कारण धार्मिक अल्पसंख्यकों और उनकी ओर से वकालत करने वालों को मनमाने ढंग से हिरासत में लिया गया, निगरानी की गई और निशाना बनाया गया।" मेरी एक पुस्तक- 'भारत के विरुद्ध पश्चिम के बौद्धिक षड्यंत्र' में "अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम, अर्थात बे-रोक-टोक धर्मोन्मूलन व ईसाईकरण" शीर्षक से एक अध्याय संक. लित है, जिसमें अनेक प्रामाणिक तथ्यों से मैंने यह सिद्ध किया हुआ है कि यह अधिनियम वस्तुत: भारत राष्ट्र के विघटन व सनातन धर्म के उन्मूलन एवं हिन्दू-समाज के ईसाइकरण-इस्लामीकरण का मिशनरी हथकण्डा और लक्षित देशों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप का अमेरिकी फण्डा मात्र है। यह आयोग इस्लामी जेहाद का भी मौन समर्थन करता है, क्योंकि ईसाइयत और इस्लाम दोनों ही धर्म-विरोधी एवं पैगम्बरवादी होने के कारण परस्पर सहयोगी हैं और इन दोनों का विरोध केवल व केवल धर्म (सनातन) से, अर्थात धर्मधारी भारत राष्ट्र व हिन्दू समाज से है।

इस अमेरिकी आयोग ने हिंदुओं के बलात यीसाइकरण व इस्लामीकरण पर कभी सवाल नहीं उठाया है; बल्कि धर्मोन्मूलन (धर्मान्तरण) विरोधी भारतीय कानूनों पर ही सदैव आपत्ति जताते रहा है, क्योंकि इन कानूनों से चर्च-मिशनरियों के विस्तारवादी अभियान में बाधायें उत्पन्न होती हैं। मालूम हो कि अमेरिका ईसाइयों की सर्वोच्च नीति-नियामक सत्ता- वेटिकन सिटी से संचालित समस्त मिशनरी संस्थाओं का संरक्षक बना हुआ है और इन संस्थाओं के प्रतिनिधि अमेरिकी सरकार की वैदेशिक नीति विषयक मार्गदर्शक हुआ करते हैं। इसी दुरभिसंधि के तहत अमेरिका पूरी दुनिया भर में स्वतंत्रता-समानता-लोकतंत्र व मानवाधिकार की निगरानी-पहरेदारी करने वाला चौधरी बना हुआ है इस चौधराहट की आड में वेटिकन चर्च का एजेण्डा क्रियान्वित करते रहता है। 'टाईम' और 'न्यूयॉर्क टाइम्स' जैसे मीडिया संस्थान भी इस दुरभिसंधि के साझेदार हैं। यही कारण है कि जिस प्रकार से यूएससीआईआरएफ को यह तथ्य व सत्य नहीं सूझता, उसी प्रकार से 'न्यूयॉर्क टाइम्स' को भी यह नहीं दिखता कि भारत-विभाजन के वक्त पाकिस्तान में तकरीबन ढाई करोड हिन्दू रह गए थे और लगभग उतने ही मुसलमान भारत में रह गये थे, किन्तु आज पाकिस्तान में शासन-संरक्षित मुस्लिम आतंक से पीडित-प्रताडित-धर्मांतरित-विस्थापित होते रहने के कारण हिन्दूओं की आबादी घट कर बीस लाख (दस प्रतिशत) से भी कम हो गई है, जबकि भारत में शासन से तुष्टिकृत-उपकृत होते रहने के कारण मुसलमानों की आबादी बढ कर पैंतीस करोड से भी ज्यादा हो गई है।

यूएससीआईआरएफ और न्यूयॉर्क टाइम्स के कारिन्दे कश्मीर केरल कर्नाटक व बंगाल में व्याप्त मुस्लिम जिहादी आंतकी अभियान के प्रति आंखें बन्दे किये हुए रहते हैं, किन्तु असम व उतरप्रदेश जैसे राज्यों में उसका प्रतिकार होने पर भ्रामक रिपोर्ट जारी करने और अनर्गल दुष्प्रचार करने में जुट जाते हैं। फिर तो इन्हीं भ्रामक रिपोर्टों को आधार बना कर अमेरिकी सरकार भारत-विषयक अपनी वैदेशिक नीतियां तय करता है और भारत में जिहाद बरपा रहे मजहबी संगठनों के प्रति सहानुभूतिजनक चिन्ता जताते हुए उनके समर्थन-संरक्षण में परो क्ष रुप से खडा हो जाता है। अमेरिकी सरकार की ऐसी चिन्ता से खतरनाक हालातों का निर्माण होता है, क्योंकि उसके प्रभाव से मजहबी जिहादी संगठनों के विरुद्ध व्यापक जनमत निर्मित नहीं हो पाता है और कार्रवाई की धार भी कमजोर हो जाती है। ऐसे में भारत सरकार को चाहिए कि वह दुष्प्रचार करने वाले अमेरिकी आयोगों और मीडिया-संस्थानों को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आईना दिखाने का काम तो करे ही।

- मनोज ज्वाला

लोकसभा चुनाव-2024

धर्म के नाम पर आरक्षण देकर संविधान तोड़ने की साजिश रचता इंडी गठबंधन

एक तरफ जहां राहुल गाँधी संविधान की किताब लेकर रैलियों में संविधान बचाने का शोर मचा रहें वहीं उनकी सहयोगी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी संविधान से खिलवाड़ कर उसके विरुद्ध जाकर न्यायालय के खिलाफ खड़ी होकर अपने ही गठबंधन अर्थात विपक्ष के नकली एजेंडे, झूठ व अफवाह फैलाने के मंसूबे का पर्दाफाश कर दिया है।पश्चिम बंगाल में इंडिया गठबंधन के घटक दल तृणमूल कांग्रेस की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा 2010 से 2024 तक राजनीतिक लाभ लेने के लिए अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के विभिन्न घटकों को ओबीसी समाज का आरक्षण काट कर के दिया गया जबकि मूल संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता । बंगाल के हाईकोर्ट द्वारा स्वयं संज्ञान लेते हुए उस आरक्षण को खत्म किए जाने पर ममता ने हाई कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार करते हुए मुस्लिम समाज को आरक्षण दिए जाने को कहा यह ओबीसी समाज के लिए बड़ा झटका है और उनका हक मारा गया जिसपर ना अखिलेश यादव बोले ना राहुल गाँधी बोले क्योंकि इन्हे केवल जाति के नाम पर राजनीतिक रोटियां तोड़नी है ।

ममता बनर्जी ने स्थिति ऐसी सृजित किया कि पश्चिम बंगाल में स्थिति संकट वाली दिखे और भाजपा बदनाम हो। कोर्ट के खिलाफ जाकर ममता ने साबित कर दिया कि उनका भारत देश और उसके संविधान में कोई आस्था नहीं केवल गद्दी और गद्दार उनकी पसंद है। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जजों के न्याय के खिलाफ सार्वजनिक कमेंट करने को लेकर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा दे। राष्ट्रपति शासन लगा देने का मतलब ममता का गेम प्लान असफल हो जायेगा । अब तक विपक्ष फ्रंट फुट पर खेल रहा था पर अब भाजपा को लोकतंत्र और संविधान की रक्षा की गुहार लगाने का बहाना मिल जाएगा। पश्चिम बंगाल में ओबीसी मतदाताओं से भाजपा की मरती शाख फिर से जिंदा हो जाएगी। उसका पिछडो में घटता जनाधार फिर से जीवित हो जाएगा। बीजेपी पिटती बाजी पलटकर जीत जाएगी। बीजेपी ने सन्देसखली से कलकुलेटेड गेम खेला था । आप ममता की गहरी राजनीतिक चाल को समझें।कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 37 वर्गों को दिए गए अन्य पिछड़े वर्ग आरक्षण रद्द कर दिया है।कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले से बंगाल में मुस्लिमों के करीब 5 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग सर्टिफिकेट रद्द होंगे। तभी कोर्ट के आदेश के ऊपर जाकर मुख्यमंत्री रहकर आदेश की अवमानना कर गई। क्या अवमानना के लिए ममता को नोटिस नहीं मिलना चाहिए ! उन्हें जेल जाना पड़ सकता है किन्तु ऐसा होगा नहीं क्यूंकि सुप्रीम लोग नहीं चाहेंगे। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद के ओबीसी सर्टिफिकेट को रद्द कर दिया है।

ममता सरकार ने 83 जातियों को शामिल कर दिया था। इनमें 73 जातियां मुस्लिम समुदाय से थीं। जिस न्यायाधीश ने पश्चिम बंगाल में मुसलमानों को ओबीसी आरक्षण से बाहर करने का आदेश पारित किया, मैं उनका आदेश नहीं मानूँगी, मैं उस आदेश को कभी स्वीकार नहीं करूंगी वह बीजेपी से प्रेरित है । बंगाल में मुस्लिम ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा। जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी ये बोल ममता बनर्जी ने अपना असली चेहरा दिखा दिया जिसके बाद देश भर के ओबीसी समुदाय में आक्रोश का माहौल हैं। वैसे यहीं ये है इंडी अलायन्स के मंसूबे। कहाँ गए आरक्षण के पक्षधर लोग जो चिल्लाते थे मोदी आरक्षण ख़त्म कर देगा और अफवाह फैला रहे है ! क्या वे ममता दीदी का विरोध कर पाएँगे ! जो दलित पिछड़ों आदिवासियों के हक का आरक्षण मुस्लिमों में बाँटना चाहती है ! ममता दीदी ने हाई कोर्ट के इस आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती देने का संकेत दिया। इसके साथ ही अपनी नकली आवाज को बुलंद करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि वह अदालत का सम्मान करती हैं, लेकिन मुस्लिमों को ओबीसी आरक्षण से बाहर रखने वाले फैसले को वह स्वीकार नहीं करेंगी। दोहरा चरित्र है यह। ममता बनर्जी का कहना है कि पश्चिम बंगाल में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा, क्योंकि इससे संबंधित विधेयक संविधान की रूपरेखा के भीतर पारित किया गया जबकि धर्म के आधार पर आरक्षण गैरसंवैधानिक है। ममता ने आज की राजनीतिक मर्यादा का निचला स्तर छू लिया। बिलो द बेल्ट पॉलिटिक्स से भी नीचे वाला स्तर। संविधान का अपमान करती साफ दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट का अपमान करती साफ दिख रही है। अपने जैसी चुनी हुई दूसरी सरकारों का असम्मान करती हुई साफ दिख रही है। अपने बराबर के मुख्यमंत्रियों का अपमान करती हुई साफ दिख रही है। केंद्र सरकार का असम्मान करती हुई साफ दिख रही है। सीबीआई का असम्मान करती हुई साफ दिख रही है। केंद्रीय सुरक्षा बलों का असम्मान करती साफ दिख रही है। सत्य का असम्मान करती साफ दिख रही है। नैतिकता के विरुद्ध खड़ी साफ दिख रही है।

न्याय के विरुद्ध खड़ी साफ दिख रही है। कानून के विरुद्ध खड़ी साफ दिख रही है। कोर्ट के विरुद्ध खड़ी साफ दिख रही है। राजनीतिक सुचिता के विरुद्ध खड़ी साफ दिख रही है। भ्रष्टाचार के पक्ष में सीधा सीधा उतर आई है। ममता ने व्यर्थ में पॉलिटिक्स करते हुए मोदी पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है। जाँच पर से लोगों का ध्यान भटकाना शुरू कर दिया है। सीबीआई पर आरोप लगाना शुरू कर दिया है।ममता के खिलाफ इस एपिसोड में न मोदी का कोई रोल है। न केंद्र सरकार का कोई रोल है। न सीबीआई का कोई रोल है। न ही राजनीति का कोई मामला है। कोर्ट के खिलाफ टिप्पणी पर फंसीं ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल सरकार ने 25753 टीचर और नॉन टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति को अवैध ठहराने के कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है, लेकिन इस मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कथित टिप्पणी उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है। दावा किया जा रहा है कि बीरभूमि लोकसभा के अंतर्गत वर्धमान के एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने अदालत खरीद ली है। रिपोर्टों के अनुसार, उच्च न्यायालय को बेच दिया गया जैसी टिप्पणी करने का दावा किया गया है। अदालत को बिका हुआ बताने के आरोप को लेकर अदालत ने वकील विकासरंजन भट्टाचार्य, अनिंद्य सुंदर दास और कौस्तब बागची द्वारा दायर तीन अलग-अलग याचिकाओं के आधार पर मामले को स्वीकार कर लिया। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली अदालत की प्रशासनिक शाखा यह तय करेगी कि मामले की सुनवाई कौन सी पीठ करेगी।

पंकज कुमार मिश्रा
जौनपुर यूपी

वोटर लिस्ट में बढ़ती महिलाएं संसद में कब बढ़ेगी?

महिलाओं का वोट 48%, फिर सीटें 14% ही क्यों? भारत की महिला मतदाता; एक ताकत है जिसे गिना जाना चाहिए। राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं और रियायतों के वादों के साथ महिलाओं के वोट हासिल करने की होड़ में हैं, लेकिन सच्चा सशक्तिकरण अभी भी मायावी है। जब तक राजनीतिक पार्टियां अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट नहीं देती, तब तक उनकी भागीदारी बढ़ाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। देश की मतदाता सूची में महिला वोटरों की तादाद लगातार बढ़ रही है। लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से टिकट नहीं मिलने के कारण वे इस अनुपात में संसद में नहीं पहुंच पातीं। मतदाताओं में आधी आबादी महिलाओं की है। पिछले 15 सालों में हिंदी बेल्ट राज्यों में उनकी संख्या में वृद्धि चुनाव परिणामों पर गहरा असर डाल रही है। इन सबके बीच एक सवाल यह भी उठता है कि भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी कम क्यों है? क्यों अब भी लगभग सभी पार्टियां महिलाओं को टिकट देने से कतराती हैं?

भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रही है। इसमें समय-समय पर हमेशा बदलाव होता रहा है। यदि हम महिलाओं की स्थिति का आंकलन करें तो पता चलेगा कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अनेक तरह के उतार-चढ़ाव आते रहे हैं और उसके अनुसार ही उनके अधिकारों में बदलाव भी होता रहा है। इन बदलावों का ही परिणाम है कि महिलाओं का योगदान भारतीय राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में दिनों-दिन बढ़ रहा है जो कि समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक सफल प्रयास है। चुनाव महिला उम्मीदवारों से जुड़े कई राजनैतिक पूर्वाग्रहों को दूर करने में मददगार साबित हो सकता है। साथ ही महिलाओं का राजनीतिक सशक्तीकरण करने भी कारगर सिद्ध होगा। तमाम प्रमुख राजनीतिक दलों की कथनी और करनी में भारी फर्क है। जब तक राजनीतिक पार्टियां अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट नहीं देती, तब तक उनकी भागीदारी बढ़ाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। लेकिन टिकटों के बंटवारे के समय तमाम दल किसी न किसी बहाने महिलाओं को चुनाव लड़ने से दूर रखने का प्रयास करते रहे हैं। जब तक यह पुरुषवादी मानसिकता नहीं बदलती, महिला आरक्षण विधेयक पारित होने के बावजूद तस्वीर ज्यादा नहीं बदलेगी। महिला मतदाता इतनी महत्वपूर्ण कभी नहीं थी जितनी अब है। महिला मतदाताओं को तेजी से एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र के रूप में पहचाना जा रहा है जो परिणामों को प्रभावित कर सकता है, महिला आरक्षण विधेयक के जल्दबाजी में पारित होने से बेहतर इसका कोई प्रतीक नहीं है।

भाजपा द्वारा ष्नारी शक्तिष पर किए गए सभी बड़े दावों के बावजूद, नवंबर में पांच राज्यों के चुनावों में उसके केवल 10 से 15 प्रतिशत उम्मीदवार मि. हलाएं थीं। यही बात उन अन्य पार्टियों पर भी लागू होती है जिनकी अखिल भारतीय उपस्थिति है। भारत की महिला मतदाता, एक ताकत है जिसे गिना जाना चाहिए। राजनीतिक दल कल्याणकारी योजनाओं और रियायतों के वादों के साथ महिलाओं के वोट हासिल करने की होड़ में हैं, लेकिन सच्चा सश. क्तिकरण अभी भी मायावी है। जब तक राजनीतिक पार्टियां अधिक से अधिक महिलाओं को टिकट नहीं देती, तब तक उनकी भागीदारी बढ़ाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। देश की मतदाता सूची में महिला वोटरों की तादाद लगातार बढ़ रही है। लेकिन राजनीतिक दलों की ओर से टिकट नहीं मिलने के कारण वे इस अनुपात में संसद में नहीं पहुंच पातीं।

मतदाताओं में आधी आबादी महिलाओं की है। पिछले 15 सालों में हिंदी बेल्ट राज्यों में उनकी संख्या में वृद्धि चुनाव परिणामों पर गहरा असर डाल रही है। इन सबके बीच एक सवाल यह भी उठता है कि भारत की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अब भी कम क्यों है? क्यों अब भी लगभग सभी पार्टियां महिलाओं को टिकट देने से कतराती हैं?

बीते लोकसभा चुनाव में 542 सांसदों में से 78 महिलाएं थीं। इनमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 11-11 महिलाएं चुनाव जीती थीं। संसद में महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने वाली भाजपा ने 417 संसदीय सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की है। इनमें 68 महिलाएं हैं। यानी पार्टी ने सिर्फ 16 फीसदी महिलाओं पर ही भरोसा जताया है। बीजेपी ने 2009 में 45, 2014 में 38 और 2019 में 55 महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। कांग्रेस ने अब तक 247 उम्मीदवारों की घोषणा की है। इसमें 35 उम्मीदवार यानी 14 फीसदी से कुछ ज्यादा महिलाएं हैं। वर्ष 2019 में कांग्रेस ने 54 महिला उम्मीदवारों को टिकट दिया था। टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में जिन 42 उम्मीदवारों की घोषणा है उनमें 12 महिलाएं हैं। लोकसभा चुनाव में कुल 96.8 करोड़ मतदाताओं में से 68 करोड़ लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 33 करोड़ यानी 49 फीसदी महिला मतदाता होंगी। 85.3 लाख महिलाएं पहली बार मतदान करेंगी। रिपोर्ट के मुताबिक, 2047 तक (2049 में संभावित चुनाव) महिला मतदाताओं की संख्या बढ़कर 55 फीसदी (50.6 करोड़) और पुरुषों की संख्या घटकर 45 फीसदी (41.4 करोड़) हो जाएगी। भारत के राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पिछले दशक की सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक है। महिला मतदाता अब चुनावों में पहले से कहीं अधिक बड़ी भूमिका निभा रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अब साक्षरता बढ़ने के कारण महिलाएं राजनीतिक फैसला लेने वाले एक अहम समूह के रूप में उभर रही हैं। महिला आरक्षण विधेयक, रसोई गैस सब्सिडी, सस्ते ऋण और नकद राशि के वितरण जैसे कदमों से महिला मतदाताओं को लुभाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से बीजेपी के वोटों में वृद्धि में मदद मिली है।

महिला वोटरों की संख्या बढ़ी है क्योंकि उनकी आबादी और शिक्षा भी बढ़ी है। राजनीतिक दलों ने भी जागरूकता फैलाने में योगदान दिया है। यह उनके भी हित में था की वो महिलाओं को जागरुक करें और मतदान के लिए प्रोत्साहित करें ताकि उनका वोट प्रतिशत बढ़ सके। महिलाओं की तरफ फोकस इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि पुरुष कई बार काम की तलाश में बाहर चले जाते हैं और ऐसे में वो मतदान के लिए अपने क्षेत्र में नहींआते हैं।" चुनाव आयोग ने भी इस दिशा में काम किया और महिलाओं के लिए बूथ तक पहुंचना और वोट डालना आसान बनाया। बूथों पर गर्भवती महिलाओं के लिए भी अलग इंतजाम किए जाते हैं। पर यह प्रगति इतनी धीमी है कि भारत अब भी कई बड़े देशों से इस मामले में पीछे है। महिला वोटर्स की संख्या में तो इजाफा हुआ है पर कैंडीडेटडे और सांसदों के तौर पर उनकी संख्या अभी भी बहुत कम है। तमाम राजनीतिक दल महिलाओं को कई स्पेशल स्कीम से लुभाने की कोशिश करते हैं। जैसे फ्री बस राइड, डायरेक्ट मनी ट्रांसफर आदि पर ज्यादातर पार्टियांउन्हें टिकट देने के मामले में कंजूसी करती हैं। छतीसगढ़ और त्रिपुरा को छोड़ दें तो ज्यादातर राज्यों में महिला सांसदों की संख्या बहुत कम है। स्वामी विवेकानन्द का मानना है ख़ कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है, वहाँ की महिलाओं की स्थिति। हमें महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए, जहाँ वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से ख़ुद सुलझा सकें। हमारी भूमिका महिलाओं की जिंदगी में उनका उद्धार करने वाले की न होकर उनका साथी बनने और सहयोगी की होनी चाहिए। क्योंकि भारत की महिला इतनी सक्षम है कि वे अपनी समस्याओं को ख़ुद सुलझा सकें। कमी अगर कहीं है तो बस इस बात की, हम एक समाज के तौर पर उनकी काबलियत पर भरोसा करना सीखें। ऐसा करके ही हम भारत को उन्नति के रास्ते पर ले जा पाएंगे।

-प्रियंका सौरभ

झारखंड में भ्रष्टाचार, जेल और नक्सलवाद के साथ ही संविधान का मुद्दा

रांची। लोकसभा चुनाव में झारखंड में भ्रष्टाचार, जेल और नक्सलवाद के साथ ही संविधान का मुद्दा जोर-शोर से गूंज रहा है। भाजपा ने भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाकर आक्रामक प्रचार अभियान छेड़ रखा है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत भाजपा के तमाम नेताओं और स्टार प्रचारकों के भाषणों में हेमंत सोरेन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, अवैध खनन घोटाला, टेंडर घोटाला, जमीन घोटाला, शराब घोटाला और कांग्रेस नेताओं के घरों से बरामद नोटों का पहाड़ छाया हुआ है। भाजपा के कुछ प्रचार विज्ञापनों में आइएनडीआइए के नेताओं के ठिकानों से बरामद नोटों के बंडल दिखाए जा रहे हैं। इनमें कहा जा रहा है कि आपके एक-एक वोट ने भाजपा को भ्रष्टाचारियों पर नकेल कसने की ताकत दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जमीन घोटाला में जेल जाने के बाद अब टेंडर घोटाला में उन्हीं की सरकार के कांग्रेसी मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया है। इससे भाजपा को चुनाव के बीच में ही एक और बड़ा मद्दा मिल गया है। कांग्रेस और झामुमो दोनों भले ही इससे असहज हैं, लेकिन इस मुद्दे पर वह भाजपा को घेर भी रहे हैं। केंद्र द्वारा सरकारी एजेसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद करने का मुद्दा उठाकर वोटरों की सहानुभूति बटोरने की कोशिश हो रही है। झामुमो ने हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी को झारखंडी अस्मिता से जोड़ने का प्रयास किया है। झामुमो ने इसे लेकर झारखंड झुकेगा नहीं..और जेल का ताला टूटेंगा.. नारा दिया है। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी सभाओं में यह अपील करती हैं कि हेमंत सोरेन को जेल भेजने वालों को जनता वोट की चोट से सबक सिखाए। कांग्रेस और झामुमो की सभाओं में यह आरोप मढा जाता है के भाजपा और पीएम मोदी संविधान को बदलना चाहते हैं। हालांकि, इसके जवाब में एससी-एसटी और ओबीसी आरक्षण का मुदा उठाते हुए पीएम समेत भाजपा के तमाम नेता आइएनडीआइए को चुनौती देते हुए कहते हैं कि कांग्रेस तुष्टीतकण के लिए एससी, एसटी और ओबीसी के हिस्से का आरक्षण अपने वोट बैंक में बांट देना चाहती है। धर्म के आधार पर आरक्षण संविधान विरोधी है और भाजपा यह होने नहीं देगी। प्रधानमंत्री यह भी कहते हैं कि किसी में हिम्मत नहीं कि मोदी के रहते संविधान को हाथ भी लगा सके। भाजपा का आरोप-लूट का कोई अवसर नहीं छोड़ा: भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी कहते हैं कि झामुमो-कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद जनता को लूटने का कोई अवसरे नहीं छोड़ा। पिछले दिनों भारी मात्रा में कैश बरामदगी होने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं किया जाना यह प्रमाण है कि वह भी लूट में हिस्सेदार हैं।

इधर, झारखंड प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश ठाकुर कहते हैं कि हम किसी भी भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करते, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाया जा रहा है, उसे जनता बखुबी देख-समझ रही है।

बांग्लादेशी घुसपैठ पर दोनों पक्ष आमने-सामने: इझारखंड के साहिबगंज, गोड्डा, पाकुड़ आदि जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठ की समस्या है। भाजपा ने इसको भी मुद्दा बनाया है। मोदी और शाह समेत प्रदेश भाजपा के भी नेता कांग्रेस व झामुमो पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं। गोड्डा के भाजपा सांसद निशिकांत दुबे कहते हैं कि आदिवासी महिलाओं से शादी कर घ ुसपैठिये यहां की संस्कृति पर भी असर डाल रहे हैं और जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। क्षेत्र में आपराधिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं । एक ओर जहां मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है, वहीं आदिवासियों की संख्या घट रही है । उधर राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन समेत झामुमो और कांग्रेस के सभी नेता इसके लिए केंद्र सरकार को ही जिम्मेदार ठहराते हैं वह तर्क देते हैं कि घ ुसपैठ रोकना केंद्रीय गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है।

मोदी और शहर जनसभा में कह रहे हैं कि नक्सलवाद कांग्रेस सरकार की देन है जबकि मोदी सरकार ने नक्सली औरतें क्यों का सफाया किया आने वाले दिनों में इन पर और भी प्रभावी कार्यवाही की जाएगी दशकों तक नक्सलियों का आतंक झेलने वाले राज्य में यह मुद्दा लोगों के मन को छूने वाला हो सकता है।

दो जून की रोटी

दो जून की रोटी
यों ही नहीं मिलती
कोई कड़ी धूप में चलाए फावड़ा,
चलाएं कुदाली
कोई करता साफ गंदी नाली ।
दो जून की रोटी
यों ही नहीं मिलती
कोई तेज धूप में खींचता रिक्शा
कोई रात-रातभर जागे
मेहनत करे कल कारखानों में....
दो जून की रोटी
किसी को मिलती बड़ी मुश्किल से तो
कोई काजू, बादाम, पिस्ता उढ़ाए
जब मेहनत और किस्मत रंग दिखाये
रे हरिया! जीवन बदल जाये ।

- मुकेश कुमार ऋषि वर्मा
फतेहाबाद, आगरा, उत्तर प्रदेश 283111

शाम सवेरे हे माँ, लेते हैं तेरा हम नाम

शाम सवेरे हे माँ, लेते हैं तेरा हम नाम।
सबसे प्यारी हमको तू , हे माँ तुमको प्रणाम।।
वन्दे मातरम, वन्दे मातरम,----------(2)
शाम सवेरे हे माँ----------।।
कश्मीर है शीश तुम्हारा, जो तेरा ताज है।
दिल्ली है दिल तेरा, जिसपे जग को नाज है।।
पंजाब, सिंधु , गुजरात, मराठा, काशी, मथुरा धाम।
सबसे प्यारी हमको तू , हे माँ तुमको प्रणाम।।
वन्दे मातरम, वन्दे मातरम,----------(2)
शाम सवेरे हे माँ---।।
राम- रहीमा,सूर- कबीरा, नानक की यहाँ वाणी।
सबको तुमने प्यार दिया है, तू है माँ कल्याणी।।
हिंदू- मुस्लिम, सिक्ख- ईसाई, सबका एक पैगाम।
सबसे प्यारी हमको तू , हे माँ तुमको प्रणाम।।
वन्दे मातरम, वन्दे मातरम,----------(2)
शाम सवेरे हे
माँ---।।
आजाद- भगतसिंह, प्रताप- शिवाजी की तू है जननी।
तेरी आन- शान के लिए जिन्होंने, दी अपनी कुर्बानी।।
तू सुजला- सुफिर- सुदर्शन, सुफला और अभिराम।
सबसे प्यारी हमको तू , हे माँ तुमको प्रणाम।।
वन्दे मातरम, वन्दे मातरम,----------(2)
शाम सवेरे हे
माँ---।।

गुरुदीन वर्मा उर्फ जी.आजाद
तहसील एवं जिला-बारां (राजस्थान)

जातीय धारा में राजनीतिक पतवार संभाले नए खेवनहार

जातीय कैनवास पर भावनाओं का गहरा रंग

पटना। मानसून में बाढ और कटाव होना ही होना है। कहीं जमीन नदियों में समा जाती है, कहीं उसमें डूबीं भूमि बाहर निकल आती है। नदियां अपनी धारा बदलती रहती है। यह प्रकति का नियम है। कुछ तो प्राकृतिक और कुछ प्रकृति से छेड़छाड़ का परिणाम। बिहार की राजनीति भी ठीक इन नदियों की तरह है। समाज की जातीय धारा। बनते-बिगड़ते समीकरण। कहीं जमीन खिसकती हुई तो कहीं फिर से बाहर निकलती हुई। यह समय लोकसभा चुनाव का है। राजनीतिक धाराओं का संगम भी है, अलगाव भी। उत्तराधिकारी के रूप में नए नाविक भी तैयार हो रहे हैं। इसमें आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी देखी जा सकती है। पुरानी पीढ़ी ने राजनीति की धारा में नाव खेने का प्रशिक्षण अच्छे से दिया है। हाथ पांव मारने को अकेला छोड़ दिया, ताकि वे उसकी गहराई को समझते हुए पार उतर सके। बाहर से उन पर दृष्टि जरूर है। इस नई पीढ़ी में कई चेहरे हैं, जो अपनी राजनीतिक जमीन बचाने की गरज से जातीय घ ेरे का बांध बनाने में जुटे हैं। श्जातीय बांधश इसलिए, क्योंकि यह यहां की राजनीति के मूल में है। वर्तमान समय में दो धड़े हैं। एक ओर एनडीए दूसरी ओर आइएनडीआइए। इन्हें मुख्य सियासी नदियां कह सकते हैं। राष्ट्रीय फलक पर गंगा और गंड़क की तरह। सहयोगी नदियों से इनकी धारा को और प्रवाह मिलता है, जो क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी हैं।

नदी की धाराओं की ही तरह राजनीति के प्रवाह को समझा जा सकता हैं। भाजपा यहां जदयू और लोजपा के साथ प्रवाहित होती रही है तो कांग्रेस राजद के साथ। वाम दल और विकासशील इंसान पाटी (वीआईपी) भी है।

भाजपा जदयू का संगम पुराना है, अलगाव भी हुआ फिर साथ-साथ। आइएनडीआइए खेमे में कांग्रेस और राजद की पुरानी संगत है। कुल मिलाकर यही राजनीतिक परिदृश्य है जिसमें राजनीतिक नौकाओं की पतवार थाम चुकी है। इनमें राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के पुत्र तेजस्वी यादव हैं तो दूसरी ओर दिवंगत हो चुके रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान। राजद की बागडोर अभी लालू के ही हाथ में है, पर नाव तेजस्वी खे रहे। चिराग अपनी पार्टी की नाव के सर्वेसर्वा बन चुके हैं। नदियों के कटाव की तरह इनकी मूल पार्टी लोजपा दो धड़ो में बंट चुकी है, जिसमें एक चाचा पशुपति कुमार पारस के नेतृत्व में हैं। हालांकि, सक्रियता दिख नहीं रही।

लोजपा (रामविलास) का नेतृत्व सीधे चिराग के हाथों में। ये दशकों की मूल धाराएं हैं, जिनमें नया नेतृत्व तैयार हो चुका है। भाजपा में सम्राट चौधरी को क्षेत्रीय उभार मिला है। चुनावी सरगमी चरम पर है। बात जातीय समीकरणों की करें तो नेतृत्व को लेकर बिहार में पिछड़े अति पिछडे और वंचित समाज के बीच ही असली लड़ाई दिख रही है।

सवर्ण का साथ किसी के लिए प्लस प्वाइंट है। मुस्लिम वोट की अहमियत भले हो, पर नेतृत्व जैसी स्थिति नहीं। इनमें कौन कितनी सहायक नादियों को जोड सकता है, वह आने वाले समय में बहुत कुछ तय करेगा। सी, जोर-आजमाइश इसी की है। पिछडे- अति पिछड़ों में यादव, कुर्मी, कुशवाहा जैसी जातियां राजनीतिक रूप से प्रभाव रखती हैं। वचितों में पासवान समाज के साथ मुसहर, रविदास आदि संख्या बल में हैं। मुसहर समाज से जीतनराम मांझी अभी स्वयं हावी हैं, बेटे संतोष कुमार सुमन को तैयार कर रहे।

तेजस्वी का पारंपरिक एमवाई समीकरण साथ है। कटाव तो यहां भी हुआ, पर पिछले विधानसभा चुनाव में ही उन्होंने बांध बांधने का भरपूर प्रयास किया। दिख रहा है। सम्राट चौधरी कुशवाहा जमीन को समेटने में जुटे हैं। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन भी है। इनके पिता शकुनी चौधरी यहां की राजनीति में प्रभावी भूमिका में थे, पर सम्राट भी अब अकेले स्वयं का अस्तित्व गढ़ रहे।

चिराग वंचित समाज का बांध बनाने में जुटे हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभा में जिस तरह उन्हें सराहा है, वह इस धारा में भविष्य का संकेत भी है। हर बड़ी नदी को सहायक नदियों की जरूरत है। वीआइपी के मुकेश सहनी भाजपा के साथ थे, वहां से कटाव हो गया तो धारा राजद संग जा मिली। स्वयं को उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट भी कर चके हैं। बात क्षेत्रीय क्षत्रपों के मुद्दों की करें तो तेजस्वी ने रोजगार को हथियार बना रखा है। चिराग आध्यात्मिक गेलियारों में भी पर्यटन के औद्योगिक विकास से रोजगार ढूंढ़ रहे। जातीय कैनवास पर भावनाओं का रंग गहरा है। राजनीतिक दलों में नई पीढ़ी लोकसभा चुनाव की जमीन पर आने वाले विधानसभा चुनाव का बिचड़ा भी अभी से बो रही है।

कैंसर के 20 प्रतिशत मामले 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में

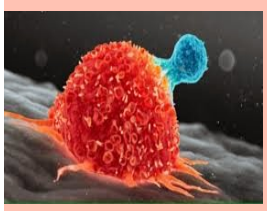

कैंसर से संबधित एक नए अध्ययन में चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। शोध के अनुसार, भारत में कैंसर के 20 प्रतिशत मामले 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में पाया गया । इनमें 60 प्रतिशत पुरुष व 40 प्रतिशत महिलाएं थी। शोधकर्ताओं ने इसके लिए युवाओं की खराब जीवनश. ली को जिम्मेदार मानाहै। शोध के अुनसार, सिर और गर्दन का कैंसर सबसे अधिक 26 प्रतिशत और इसके बाद पेट, लिवर जैसे गैस्ट्रोइन्टेस्टाइन कैंसर की भागीदारी 16 प्रतिशत पाई गई । 15 प्रतिशत मामले ब्रेसट कैंसर व नौ प्रतिशत ब्लड कैंसर के थे।

दिमाग की मेहनत पर निर्भर स्मरण शक्ति

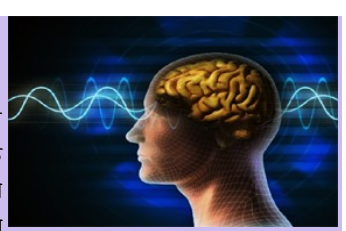

क्या आप कभी सोचते हैं कि ढेर सारी सूचनाओं के बीच आपका मस्तिष्क कुछ बातों को ही क्यों याद रखता है। एक अध्ययन में बताया गया है कि यह इस बात पर निर्भर हो सकता है कि मस्तिष्क को कितनी मेहनत करनी पड़ी है । अमेरिका में येल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने इसे समझने के लिए महत्वपूर्ण प्रयोग किए। नेचर ह्युमन बिहेवियर पत्रिका में प्रकाशित निष्कर्षों से पता चला कि मस्तिष्क पहले से अनुमानित घटनाओं को याद नहीं रख पाता। येल के कला और विज्ञान संकाय में मनोविज्ञान के सहायक प्रोपफेसर इल्कर यिल्डिरिम के अनुसार दिमाग उन चीजों को याद रखने को प्राथमिकता देता है, जिन्हें वह बहुत अच्छी तरह से समझाने में सक्षम नहीं है। यदि कोई दृश्य पूर्वानुमानित है और आश्चर्यजनक नहीं है, तो उसे अनदेखा किया जा सकता है। टीम ने प्रयोगों की एक श्रंखला तैयार की, जिसमें लोगों से पूछा गया कि क्या उन्हें तेजी से दिखाई गई तस्वीरों के अनुकरम से विशिष्ट तस्वीरे याद हैं।

बेटियाँ

पायल छनकाती बेटियां
मधुर संगीत सुनाती बेटियां
पिता की साँस बेटियां
जीवन की आस बेटियां।
हाथों की लकीर बेटियां
राखी की डोर बेटियां
उचाईयों को छू जाती बेटियां
होसला बढ़ा जाती बेटियां।
चाँद -तारों से प्यारी बेटियां
उम्मीद की किरण बेटियां
मेहंदी रचाती रहती बेटियां
ख्वाबो के रंग सजाती बेटियां।
ससुराल जब जाती बेटियां
यादें घरों मे छोड़ जाती बेटियां
जब -जब संदेशा भेजती बेटियां
मन को खुश कर जाती बेटियां।
आँखों मे सदा ही बसती बेटियां
आंसू बन संग हमारे रहती बेटियां
मातापिता का बनती सहारा बेटियां
मजबूत रिश्तों का बंधन होती बेटियां।

संजय वर्मा 'दृष्टि'
मनावर जिला -धार (म.प्र.)

घूँघट की बगावत

26 मई 2024

प्रत्येक रविवार को प्रकाशित
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र

लोकसभा चुनाव-2024

महिला मतदाताओं की संख्या अधिक होने के बाद महिला उम्मीदवार मात्र बारह

गुवाहाटी। असम में महिला मतदाताओं की संख्या अधिक होने के बावजूद 12 महिला उम्मीदवार 2024 लोकसभा चुनाव के लिए चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमाने में लगी हुई है जबकि पिछली बार 14 महिला प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा था। यह 12 महिला उम्मीदवार राज्य में 14 लोकसभा चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों में से सात में चुनाव लड़ रही है। असम में कुल 2,45,72,144 मतदाता हैं । जिनमें से 12,33,924 महिला और 1,23,25,293 पुरुष मतदाता है। महिला मतदाताओं की संख्या अधिक होने के बावजूद महिला प्रत्याशियों की संख्या में

गिरावट 2014 से जारी है जब 16 महिलाओं ने चुनाव लड़ा था। भाजपा एक महिला उम्मीदवार बिजुली कालिता मेधी को प्रतिष्ठित गुवाहाटी सीट से टिकट दिया है जबकि विपक्षी दल कांग्रेस में गुवाहाटी में मीरा बोर ठाकुर गोस्वामी कथा काजीरंगा में रोज लीना टिर्की को उम्मीदवार बनाया है। छोटे दलों में गण सुरक्षा पार्टी ने दो महिलाओं जबकि हिंदू समाज पार्टी, गन संग्राम परिषद सोशलिस्ट यूनिटी सेंटर ऑफ इंडिया (कम्युनिस्ट) तथा वोटर्स पार्टी ने एक-एक महिला उम्मीदवार और तीन महिला निर्णतन प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रही हैं। काजीरंगा में सर्वाधिक तीन महिला प्रत्याशी हैं उसके बाद कोकराझार में गुवाहाटी में 22 और सोनितापुर दारांग उदालगुरी नगाव बार पेटा और धुबरी में एक-एक महिला प्रत्याशी है

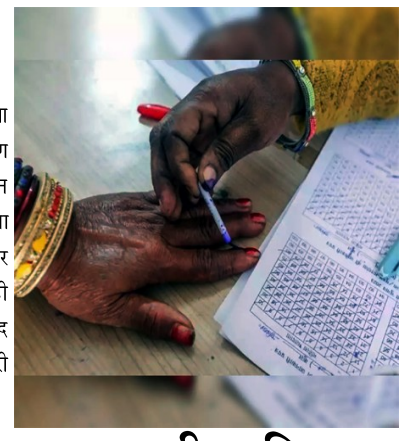

एक भी महिला प्रत्याशी नहीं

डुमरियागंज। डुमरियागंज संसदीय क्षेत्र में आजादी के बाद में चुनाव में अभी तक चुनाव महिला प्रत्याशी नहीं जीत पाई। विस्मरण है कि यहां से कुछ है बार गद्दा और महिला प्रत्याशियों ने दावेदार की थी लेकिन वह मतदाताओं की पहली पसंद नहीं बन सकीं। वर्ष 1991 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में यहां पर वरिष्ठ नेत्री मोहसिना के दोहे को अपना उम्मीदवार बनाया था परंतु वह दूसरे स्थान पर रहते हुए चुनाव हार गई थी इसी चुनाव में इंडियन कांग्रेस (सोशलिस्ट) अपने नाम की महिला पत्रकार सीमा मुस्तफा को टिकट दिया था जब चुनाव में जमानत भी नहीं बचा सकीं। 1996 में लोकसभा चुनाव में महिला प्रत्याशी मोहसिना किदवई दोबारा चुनाव मैदान में उतारी इस बार-बार एनडीटी गुट (कांग्रेस) की प्रत्याशी थी जब किसी में मुस्तफा दोबारा निध नों उम्मीदवार के रूप में सामने आई दोनों की जमानत जप्त हो गई। इस चुनाव में मोहसिना की दवाई पांचवी और सीमा मुस्तफा 10 में स्थान पर रही। 2014 के संसदीय चुनाव में कांग्रेस ने महिला प्रत्याशी के रूप में बंसी राजघराने की रानी वसुंधरा को टिकट दिया था लेकिन उन्हें भी कामयाबी नहीं मिल पाई उन्हें मात्र 9.42 प्रतिशत ही वोट मिले और जमानत जप्त हो गई। वैसे इस संसदीय सीट से प्रमुख दलों में अब तक के चुनावी इतिहास में सिर्फ कांग्रेस ने ही महिला उम्मीदवार को चुनाव लड़ने की हिम्मत दिखाई ।

जबरा मारे रोने भी ना दे

भारत में इस बार मतदान में कुछ मतदाताओं ने यदि उदासीनता दिखाई है तो वह सत्ताधारियों को हल्की चेतावनी भेज दी है कि वह आत्म मंथन करें। सदैव दूसरों में गलती ना खोजें। कम मतदान के मामले में कभी दूसरों की दृष्टि से भी देखना चाहिए। दलों उम्मीदवारों की गुणवत्ता और उन्हें ही अधिक जिम्मेदार बनाने पर सोचना चाहिए। यदि सत्तारूढ दल खुद ही 400 ऊपर के दावे कर रहा हो तो मतदाताओं के एक वर्ग में उनका मत व्यर्थ मानने का भाव आना स्वाभाविक है घर में आग हमेशा दुश्मन नहीं लगता कभी लापरवाही में वह घर के चिराग से भी लगती है। इसी बीच मतदान को अनिवार्य करने का विचार भी चर्चा में है।

मतदान न करने का निर्णय भी एक मत है इसका भी सम्मान होना चाहिए यही प्रतिष्ठित लोकतांत्रिक देश में भी प्रचलित है मतदान को जबरिया बनाने की बातें जले पर नमक छिड़कने जैसी हैं कि जबरा मारे और रोने भी ना दे।

देश में जारी आम चुनाव के दौरान मतदान के घटते रुझान पर व्यापक चिंता व्यक्त की जा रही है जबकि कई लोकतांत्रिक देश में कम मतदान एक सामान्य परिघटना मानी जाती है। पूर्व की तुलना में घटता मतदान सदैव नकारात्मक नहीं बल्कि मिले-जुले संकेत भी देता है इसका सकारात्मक अर्थ इससे भी निकाला जाता है कि लोग बहुत शुद्ध नहीं है सामान्य से अधि क मतदान अक्सर जनक क्रॉस से भी उरत है और सत्ता बदल देता है। इसीलिए यूरोपीय देशों में सत्ताधारी नेता कम मतदान से नहीं अभी तो अधिक मतदान से आशंकित होते हैं। यह सब एक तरफापन है जिसमें केवल दलों और नेताओं की सुविधा का ध्यान रखना ही प्राथमिकता होती है। उदाहरणार्थ- उम्मीदवार एक से अधिक चुनाव क्षेत्र से खड़े हो सकते हैं लेकिन मतदाता केवल एक ही क्षेत्र में मतदान कर सकता है जबकि किसी नेता द्वारा दो जगह से चुनाव लड़ने में पहले से तय हो जाता है कि वह पूरे क्षेत्र में फिर मतदान भारी समय और धन की बबार्दी हो सकती है यदि विजय उम्मीदवार ने उसे क्षेत्र से जीत कर वहां से त्यागपत्र दे दिया तो लाखों लोगों का मत बेकार हो जाता है। जनता को फिर से उपचुनाव में मतदान करना होगा।

आवश्यकता चुनाव प्रक्रिया को सरल सस्ता जिम्मेदार गुणवत्ता परत बनाने की है। तब सोता मतदान अधिक सार्थक होगा और उसके प्रति आकर्षण बढ़ेगा। विचारणीय है कि ऐसे सुधार पर विचार होना चाहिए जिसमें समाज का व्यापक हित हो सदैव खंडित स्वार्थी डेली वर्गिहित के लिए तरह-तरह के प्रपंच से हटकर भी विचार करना अनिवार्य है इसके लिए ऐसा चुनाव सुधार सुरेश कर होगा जो चुनाव प्रक्रिया में बेतहाशा खचीर्लापन रोकने पर ध्यान केंद्रित करते हुए हर तरह के योग्य लोगों को प्रोत्साहन प्रदान करें। दलिया मनमानियां पर लगाम लगे चुनाव प्रचार बिल्कुल संक्षिप्त और संयमित किया जाए ताकि उसके लिए अधिक धन की आवश्यकता ही खत्म हो जाए। तमाम आडंबरों पर रोक लगाई जाए यानी चुनाव को सरल किंतु गंभीर कम बनाया जाए चाहे कुछ उत्सव भाव भी रहे लेकिन महंगे रोड शो अनावश्यक प्रदर्शन बंद हो झूठी या निराधार बयान बाजी पर सांकेतिक ही सही किसी दंड या उत्तरदायित्व की पक्की व्यवस्थापना बने।

सांसद और विधानसभाओं की कार्यवाहियों में दलबंदी का खुला प्रदर्शन रोका जाए हर कहीं स्वस्थ गतिविधियों जिम्मेदार सहयोगी और सकारात्मक बातों की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित किया जाए ऐसे सुधारो पर सभी दलों को गंभीर तापूर्वक नियत के साथ मिलकर सोचना चाहिए तब चुनावी प्रक्रिया में लोगों की रुचि बढ़ेगी।हमारे राजनीतिक दल और नेता कितनी भी छुद्रता दिखाएं लेकिन अपने लिए सबसे तालियां चाहते हैं। दलों द्वारा दुष्प्रचार आडंबर सौदेबाजी भ्रष्टाचार छल प्रपंच एक दूसरे पर गणित आप आदि के होते उन्हें चुनने के लिए सबसे उत्साहित होने की मांग जबरदस्ती ही है। आज का दृश्य क्या बेहतर है अभी कुछ लोग अपने दल के नारे और अपनी नीतियों के लिए प्रतिबंधित दल को दोष दे रहे हैं वर्षों से यही हाल है कि कुछ नेता सालों साल जैसे चुनावी भाषण ही देते रहते हैं सदैव चुनौती और निंदा से भारी लाफा जी वह विदेश में बोलते हुए भी अपने प्रतिद्वंद्वी दल या नेताओं पर आकर करते हैं। हमारे नेता कभी भी समाज की विभिन्न आवश्यकताओं समस्याओं या विवादों पर कोई गंभीर विचार विमर्श करते हुए नहीं मिलते। मानव जिम्मेदारी लेकर सबको साथ जोड़कर कोई रचनात्मक विमर्श उनका काम ही नहीं है। उनका काम तो मानो केवल एक दूसरे को नीचे दिखाना और मनमाने वादे करना भर है। चुनावी घोषणा पत्र के नाम पर पूरी सैद्धांतिक बातें लच्छेदार वादे या हवा हवाई बातें अब तो सीधे लालच देकर मतदाताओं के किसी वर्ग को लुभाने जैसे प्रस्ताव भी आने लगे हैं। यह भी एक विचित्र दृश्य ही है कि मूलत: एक जैसी आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक प्रादेशिक नीतियां रखते हुए भी वह दूसरों की निंदा करते हैं जिन नीतियों को स्वयं गलत कहते रहे स्वयं सत्ता पाने पर वही नीति जमकर चलाते हैं अथवा ऐसे काम करते हैं या घोषणाएं कर देते हैं जिनका कभी घोषणा पत्र में उल्लेख ही नहीं किया था फिर बात-बात में श्रेय लेने की लालसा और तरह-तरह की टिकट में भेद न सभी नारे अपनी पार्टी या नेता केंद्रित गणना सार्वजनिक स्थानों पर भी केवल दलीय नेताओं के नाम थोपना क्या है वह स्थान तकनीक व्यापार साहित्य कला खेल कूद से संबंधित क्यों ना हो। राजनीतिक गतिविधियों में नित्य अवस. रवादी जोड़-तोड़ गठबंधन करने अपनी पिछली बातों को स्वयं झूठा साबित करते रहना एक दूसरे पर कीचड़ उछाल कर फिर गद्दी के लिए मिल जाना जिन कामों की एकमात्र जिम्मेदारी उनकी है उससे मुंह चुरा कर दूसरों को ललकारना दोस देना उलाहना और फटकारना सब काम नेता थोड़े ही कर सकते हैं कुछ जनता को भी करना चाहिए।

अधिकारों का कर्तव्यों के प्रति सजग रहना होगा मतदाताओं को

शिक्षा स्वास्थ्य सेवाओं के बजट पर चर्चा होती है तो किसानों मजदूरों और डिग्री धारकों के भविष्य पर चर्चा भी होनी चाहिए ऐसे में जनप्रतिनिधियों की चुप्पी हो तो चौकाती ही है। डॉ. जागेश्वर चतुर्वेदी ने अपनी पुस्तक हिंदी पत्रकारिता के इतिहास की भूमिका के पेज 85 अध्याय भारतेंदु युगीन पत्रकारिता का प्रत्यक्ष में लिखा है कि आधुनिक युग में संस्कृत और राजनीतिक नाभिनालद्वय है जो लोग संस्कृत और राजनीति में संबंध नहीं देखते। अब समाज के प्रति समग्र दृष्टिकोण पैदा भी नहीं कर सकते। इन दोनों परिवारवाद बड़ा मुद्दा है। जातिवाद उन्मूलन बड़ा मुद्दा नहीं है। भ्रष्टाचार मुद्दा नहीं है यह विषय गंभीर है। इस पर राष्ट्रीय बहस होनी चाहिए मतदाताओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति सचेत रहना होगा। मौजूदा लोकसभा चुनाव मुद्दा विहीन है। जब कोई चुनाव मुद्दों पर आध ारित होता है तब पक्ष और विपक्ष के लिए बहस आसान होती है। सत्ता पक्ष के पास अपने अनेक कार्य गिरने का अवसर चुनाव के समय होता है। सत्ता पक्ष द्वारा अपने पक्ष में रखी जा रही बातों के प्रशंसा का मंच चुनाव होता है । सत्ता रूढ दल अपने कार्यों को बताकर यदि चुनाव का मे ला उठाता है तो यह उसका अधिकार भी है। विपक्षी के पास सत्ता दल को घेरने के लिए मुद्दे होने चाहिए। इस लोकसभा चुनाव में विपक्ष किसी भी समस्या को मुद्दा नहीं बन पाया । सच तो यह है कि कोई भी सरकार अपने कार्यों से बोलती है और विपक्ष माइक से बोलता है। पूरे 5 साल विपक्ष मुद्दा आधारित लोकगीत के विचार सदन के भीतर और बाहर नहीं रख पाया ना ही आंदोलन से अपने पक्ष में वातावरण बना पाया। जनहित की बातों और समस्याओं को लेकर लोकसभा में सकारात्मक चर्चा भी ठीक नहीं रही। प्रिया बिंदुओं पर जहां विपक्ष भगत रहा वहीं इसका लाभ सत्ता दल को लगातार मिलता देखा गया प्रयास सत्ता दल की किसी छोटी सी बात या टिप्पणी पर विप क्ष भ्रमित होता देखा गया।

वह संख्या का आबादी नहीं जानती कि उनके संवैधानिक अधिकार क्या है? आज भी प्राय लोग मानते हैं कि संसदीय विधायक पुलिस तहसील में सिफारिश करने के लिए उपयुक्त है। लोकसभा में जब कोई विधायक लाया जा रहा हो तब सांसदों की क्या भूमिका होती है देश की जनता पराया नहीं जानती सांसद और विधानमंडल की कार्यवाही में जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी किया है इसे लेकर शिक्षित और प्रबुद्ध समाज भी गंभीर नहीं है जब बेरोजगारी पर बात होती है। जनहित पर चर्चा लोकसभा और विधानसभा मंडल के साधनों में नहीं होने चाहिए सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ताओं में निराशा होती है। सच्चा दिल को इसका लाभ मिलता है राष्ट्र का नुकसान होता है खास बात यह भी है कि सदन के भीतर माननीय सदस्यों को मर्यादित रहने सदन को सुख व्यवस्थित चलने संसदीय व्यवस्था के अनुसार आचरण करने के प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। सत्र के एक-दो दिन पूर्व सर्वदलीय बैठक और साथ में सत्ता दल द्वारा सदन के सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक का आयोजन भी किया जाता है मगर सदन के पहले दिन ही हंगामा शुरू हो जाता है सदन चलाने में मोती की ध नराशि खर्च होती है अपने नेता के प्रति वफादारी दिखाने का अवसर सदन में मिलता है वह इस स्वर्णिम अवसर को खोना नहीं चाहते। चुनाव में जनमानस इस बात का मूल्यांकन करता है कि उसके क्षेत्र के सांसद और विधानसभा में सदन में नए कानून पर कितनी चर्चा की क्या कोई ऐसे सुझाव दिए जो राष्ट्र निर्माण के लिए सुंदर हैं क्या शिक्षा को लेकर कोई विषय रखा क्या सदन में पर्यावरण की चिंता की नदियों में प्रदूषण को घ टाना पर कोई उपयोगी सुझाव दिए क्या इस बात पर चर्चा हुई कि किसानों की फसल का अधिकतम लाभ कैसे मिले? इस पर कितने सांसदों और विधायकों की राय आई प्रश्न प्रति प्रश्न हुए सरकार का प्रश्नों में क्या रख रहा? विधान परिषद सदस्य स्नातक क्षेत्र के भी होते हैं तो भी स्नातकों की बात क्यों नहीं होती है सदस्यों ने सदन के भीतर यह जरूर बताया होगा कि किस के बेटे हैं गांव से आए हैं भारत गांव में ही है बेरोजगारी को लेकर सांसदों विधायकों की राय सामने नहीं आती है ना लोकसभा में और विधानसभा में। आखिर यह विषय आते क्यों नहीं विपक्ष बोलता नहीं सत्ता मौन रहता है जबकि शक्तियों की बात की जाए तो विधायक एमएलसी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य चाहे वह सत्ता दल के हो या विपक्ष के समान शक्तियों से लैस हैं मगर वह प्राय नहीं बोलते उनके अंदर प्रश्न नहीं उठाते सदन के भीतर अपने क्षेत्र की अपेक्षा करते हैं वह प्रश्न अनुकूल नहीं होते हैं। वह उनके लिए भी विचलित नहीं होते जिनके वोट से पदासीन होते हैं। उपनिषदों में एक उपनिषद है प्रश्न उपनिषद वह इस उससे भी प्रेरित नहीं होते वह किसी सरकारी अस्पताल में चिकित्सक की कमी को भी देखकर सज्जनों में समस्या नहीं रखते हैं बाद चिकित्सा शिक्षा या नई ट्रेन चलाने की बस चलने नदियों पहाड़ों को बचाने की नहीं है मूलभूत प्रश्न यह है कि संसद विधान मंडल में जब गांव गरीब मजदूर बेरोजगारी दवा अपराध न्याय की चर्चा में भागीदारी नहीं होगी तो उपाय क्या है?

घूँघट की बगावत
(हिन्दी साप्ताहिक)
द्वारा जनहित में जारी

प्रिय पाठकों,

इस अंक में प्रकाशित सभी अग्रलेख, कथा–लघु कथा, कविता, व्यंग्य, विचार विमर्श लेखकों एवं विचारकों की अपनी कल्पना प्रसूति हैं। त्रुटियां मानवीय स्वभाव का अंग हैं जिनकी ओर ध्यान आकृष्ट करना एक जागरूक पाठक की विशेषता होती है।

अतः आप सभी सुधी विज्ञजनों, से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि आप अपने पत्रों के माध्यम से इस अंक में प्रकाशित त्रुटियों की ओर ध्यान आकृष्ट भी समय–समय पर कराते रहें ताकि उन त्रुटियों की पुनरावृत्ति से बचा जा सके।

विवाद की स्थिति में न्यायालय, गोर खपुर का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

–व्यवस्थापक

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक पंकजधर द्विवेदी द्वारा जनप्रकाशन प्रेस, निकट रीड्स साहब का धर्मशाला से मुद्रित एवं 45 बादशाहबाग, जगन्नाथपुर, गोरखपुर से प्रकाशित। सम्पादक–पंकज धर द्विवेदी सम्पर्क सूत्र– e-mail- ghoonghatkibagawat37@gmail.com